



Shraddha Kapoor's Cryptic Emotional Note Leaves Fans...

SARAF	
सोना	: 9,110
चांदी	: 119.0

(नोट : सोना 22 केरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

भारत ने मलेशिया को हराकर जीता एशियाई स्नूकर में गोल्ड मेडल

COLUMBO : कई दफा के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी और बृजेश दमानी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने शनिवार को यहां एसीबीएस एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में मजबूत मलेशिया को 3-1 से हराकर टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने पिछली बार दो साल पहले ईरान में स्वर्ण जीता था। इस तरह यह भारत का पांचवां स्वर्ण पदक है।

कोलकाता गैंगरेप : प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री सुकांत हिरासत में लिए गए

KOLKATA : कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। शनिवार को इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह घटना गडिंयाहाट क्रॉसिंग, दक्षिण कोलकाता में हुई, जहां भाजपा कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सुकांत मजुमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पुलिस ने यह कार्रवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर की है।

राजधानी के कई इलाकों में आज बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

RANCHI : विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल अशोकनगर के अंतर्गत अशोकनगर पावर हाउस से निकलने वाले 11 केवी न्यू वे फीडरों में रविवार को दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक पेड़ की डालियों की छटाई की जाएगी। इस वजह से इस अवधि में अगरोड़ा चौक, बुध विहार, अशोक विहार, अशोकनगर एक्सप्रेसटेशन, सेंट्रल अशोका सहित अन्य, इलाकों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस संबंध में बिजली विभाग ने संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं से विद्युत से होने वाले जरूरी कार्यों को पहले पूरा करने का आग्रह किया है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

NEW DELHI : दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इनमें से पांच 'ट्रांसजेंडर' के शेष में रह रहे थे। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से सात के फोन में प्रतिबाधित मैसेंजिंग ऐप मिले हैं जिनके जरिये वे बांग्लादेश में अपने परिजनों से बात करते थे।

नौकरशाही



डॉ. बृजेश मिश्र

झारखंड की नौकरशाही में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा हालिया तबादलों को लेकर है। कहा जा रहा है कि नए दायित्व वितरण में एक साथ कई पैमानों पर परीक्षण हुआ है। क्या कुछ चर्चा रहा है अंदर-बाहर, जानें द फोटोन न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर की कलम से।

बाबा का आशीर्वाद

काफी पहले एक फिल्म आई थी 'वक्त', गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ था... वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। जी हां, आदमी को चाहिए कि वक्त से डरकर चले। कब किसका कैसा वक्त होगा, यह तो वक्त-वक्त की बात है। कुछ ग्रह-नक्षत्र की भी बात होती है। अब इन साहब को देखिए। राज्य में अच्छी-भली योजना को संभाल रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि ज्ञान की दुनिया को 'आदित्य' की रोशनी से रोशन कर देंगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि वक्त खराब हो गया। गुरुजनों के पहनावे पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया। जिन गुरु के चरण स्पर्श को पुनीत कार्य माना जाता है, उनके चरण के पहनावे को लेकर चर्चा चरम पर पहुंच गई। फिर क्या था। वक्त खराब होना ही था। हो भी गया। उसी बीच हुक्मरान ने नौकरशाही को मथ दिया। साहब भी मथाकर किनारे लग



गए। कुछ समय शांत रहे। वक्त का इंतजार किया। फिर अपना वक्त ठीक करने की जुगत में लग गए। कहा जाता है कि वक्त खराब हो तो निराश नहीं होना चाहिए। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। कुछ ऐसी ही सोच रही होगी। किनारे लगे थे सो तिनके का सहारा चाहिए था। मन से ईश की वंदना करते रहे। कुछ उम्मीद की किरण जगी। नव प्रभात चाहिए था। सहारा मिला। वक्त बदलने का वक्त आ गया था। अब जरूरत बाबा के आशीर्वाद

की थी। बिना आशीर्वाद के भला कहीं कुछ होता है...। फिर शुरू हुई बाबा के दर की दौड़। वो कहा जाता है न, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे दिलाने में जुट जाती है। बाबा के दर तक दौड़ का फलाफल मिलने का वक्त आ गया। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। अब तलाश थी तो एक अदद कुर्सी की। माथापच्ची शुरू हुई कि किसकी कुर्सी खाली कराई जाए, जहां साहब की ताजपोशी की जा सके। तलाश

भी पूरी हो गई। कोयले वाले इलाके को इसके लिए पसंद किया गया। वाकई, वक्त बदल गया। सामूहिक प्रयास रंग लाया। बरसात में जलाशय लगाव है। तालाब में पंकज खिल रहा है। ऐसे में गुरु की कमी कहीं खल रही थी। उनसे बात होती तो कुछ दिव्य ज्ञान और प्राप्त हो जाता। न जाने इन दिनों कहां खो गए हैं कि मुलाकात नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, जाएंगे कहां। बात तो होगी ही। गुरु का ज्ञान नहीं, बाबा का आशीर्वाद सही।

जैन संत आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्मशताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले-

संतों के अमर विचारों से भारत सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता

NEW DELHI • PTI : शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत अपने संतों और ऋषियों के अमर विचारों व दर्शन के कारण दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज जी की जन्मशताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं आचार्य विद्यानंद महाराज के विचारों से प्रेरित हैं। कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था और संस्कृति मंत्रालय ने भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट, दिल्ली के सहयोग से देश के सबसे प्रतिष्ठित जैन आध्यात्मिक नेताओं, विद्वानों और समाज सुधारकों में से एक की 100वीं

केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं आचार्य विद्यानंद के विचारों से प्रेरित

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति तक पहुंचे कल्याणकारी योजनाएं



साहित्य एवं संगीत में योगदान को सराहा

मोदी ने आचार्य विद्यानंद महाराज जी की विरासत और प्राकृत भाषा के पुनरुद्धार, कविता में मोदी के जीर्णोद्धार तथा साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जीवन विद्या और आनंद का अद्वितीय संगम था। उन्होंने कहा, हमारा भारत दुनिया की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यता है, जो हमारी सालों से अमर है, क्योंकि हमारे विचार अमर हैं, हमारी सोच अमर है।

विषम परिस्थिति में भारत ने दुनिया को अहिंसा की ताकत से कराया परिचित

सेवा और मानवता ही मूल भावना

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, जहां सेवा और मानवता इसकी मूल भावना के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा, हमारी साल पहले जब दुनिया ने हिंसा का जवाब हिंसा से देने का मार्ग चुना था, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की ताकत से परिचित कराया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने मानवता की सेवा की भावना को सर्वोपरि रखा है। सेवा करने का हमारा तरीका बिना किसी शर्त के और स्वायं से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाह वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना हो या अन्य ऐसी कल्याणकारी योजनाएं - ये सभी समाज के अंतिम पलिके के व्यक्ति के प्रतिसेवा की भावना की दशाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी को एक साथ आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, यही आचार्य विद्यानंद महाराज जी की प्रेरणा है और यही हमारा संकल्प है।

जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया था। विद्यानंद महाराज का जन्म 22 अप्रैल,

1925 को बेलगामा (अब कर्नाटक में) के शेडबल में हुआ था। उन्होंने जैन दर्शन,

राम मंदिर निर्माण कार्य जुलाई के अंत तक पूरा होने की संभावना : नृपेंद्र मिश्र

AYODHYA • PTI : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को बताया कि मंदिर निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण में है और निर्माण से संबंधित सभी प्रमुख कार्यों के जुलाई के अंत तक पूरा होने की संभावना है। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने शनिवार को अयोध्या पहुंचे मिश्र ने संवाददाताओं को बताया कि मंदिर और उसके परकोटे के लिए 14 लाख घन फुट बंसी पहाड़पुर पथर की जरूरत थी, जिसमें से 13 लाख घन फुट पथर लग चुके हैं। उन्होंने

खिड़कियों में टाइटेनियम धातु का लेखा इस्तेमाल

मिश्र ने कहा, भारत में पहली बार किसी मंदिर की खिड़कियों में टाइटेनियम धातु का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अपने आप में अनूठी बात है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस धातु की आसानी पर महज 1000 साल से भी ज्यादा समय तक टिकी रह सकती है। उन्होंने कहा, राम मंदिर निर्माण समिति को उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक सभी बड़े निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे।

कहा कि अब केवल एक लाख घन फुट पथर ही लगने शेष हैं।

गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 34 लोगों की गई जान

NEW DELHI : गाजा में इजरायल की ओर से किए गए नए हमलों में कम से कम 34 लोगों की मौत हुई है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। फलस्तीनियों को गाजा में बढ़ते मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, संघर्ष विराम की संभावनाएं भी धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। इजरायल ने यह हमले शुक्रवार देर रात शुरू किए जो शनिवार सुबह तक जारी रहे। इन हमलों में गाजा सिटी के फलस्तीन स्टैंडियम में 12 लोगों संघट कई की मौत हो गई। शिफा अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार इस स्टैंडियम में विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया था।

छत्तीसगढ़ में 23 लाख के 13 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर

AGENCY BIJAPUR : शनिवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिविजन कमेंटी में कंपनी नंबर 2 में सक्रिय 23 लाख के 13 इनामी नक्सलियों ने शनिवार को आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान बीजापुर रेंज के केंद्रीय रिजर्व पुलिस डीआईजी बीएस नेगी, बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव सहित सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी और बस्तर फाउंडर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आत्मसमर्पित 13 नक्सली पिछले कई सालों में बस्तर में हुई अलग-अलग वारदातों में कंपनी नंबर-2 की पार्टी सदस्य, एससीएम,

- एक जनवरी 2025 से अब तक बीजापुर जिले में 270 नक्सली किए गए सरेंडर
- 241 ने किया आत्मसमर्पण मुम्बई में गार जा चुके हैं 126 नक्सली
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टीवीट कर कहा, विकीरा की राह ही भविष्य का सही विकल्प



केएएमएस अध्यक्ष सहित अन्य पीपलजीए, एलओएस सदस्य शामिल थे। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सलियों के कंपनी नंबर दो की पार्टी सदस्य देवे मुचाकी ऊर्फ प्रमिला पर 8 लाख, एरिया कमेटी सदस्य कोसा ओयाम ऊर्फ राजेन्द्र पर 5 लाख, कोसी पोडियाम पर 2

लाख तथा सम्मी सेमला, छोट्ट परसीक, मोती ताती, सुनीता हेमला, मंजुला कुंजाम, सायबो पोडियम और हुंगी उपडम ऊर्फ राधा पर एक-एक लाख का इनाम घोषित है। इसके इनके अलावा मंगा मडुकम मिलिशिया प्लाटून सदस्य, बुधराम कोडमे मिलिशिया प्लाटून, जमली

कोडमे केएएमएस सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि एक जनवरी, 2025 से अब तक बीजापुर जिले में 270 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 241 ने आत्मसमर्पण किया और 126 मुठभेड़ों में मारे गए हैं।

न्यू स्टडी

वैज्ञानिकों के नए रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

मौसम की गति के असर से बदल जाती है झीलों की आकृति

PHOTON NEWS • RESEARCH DESK :

धरती, पहाड़, समुद्र, नदियां, झरने और झील मानव जीवन के लिए कुदरत के अमोल्य उपहार हैं। इन सबसे मानव जीवन प्रभावित होता है और मानव जीवन की गतिविधियों से इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। ये सभी जीवों हैं और जलवायु में परिवर्तन पर इनकी संवेदनशील प्रतिक्रिया होती है। हाल में हुए रिसर्च से यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि मौसम में परिवर्तन की गति का झीलों की आकृति पर प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि न झीलें केवल स्थिर जलराशि नहीं होती, बल्कि जीवंत और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हैं। मौसम के हर छोट्टे-बड़े बदलाव पर प्रतिक्रिया देती हैं। बांगोर यूनिवर्सिटी (ब्रिटेन) और चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत झीलों की सतह का आकार मौसमी बदलावों के अनुसार घटता-बढ़ता है। यह अध्ययन वर्ष 2001 से 2023 के बीच 14 लाख झीलों पर निगरानी के आधार पर तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों ने उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से झीलों की सतही सरचना पर बारीकी से नजर रखी।

बांगोर व सिंगुआ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने लंबे समय तक किया अध्ययन

एआई आधारित डीप लर्निंग » व लार्ड परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का किया गया इस्तेमाल	दुनिया की 14 लाख झीलों » का कई स्तरों पर किया गया व्यापक विश्लेषण	विश्व की लगभग 90 » फीसद जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में करती है निवास	तकरीबन 60 प्रतिशत » झीलों की सतह के आकार में पाया गया परिवर्तन
---	---	---	--

उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से लेवस की सतही संरचना पर बारीकी से रखी गई थी नजर

टेक्नोलॉजी ने रिजल्ट को बनाया सटीक शोध में कुत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित डीप लर्निंग और हार्ड-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का सहारा लिया गया। इससे यह विश्लेषण संभव हुआ कि वर्ष भर के मौसम सर्दी, गर्मी, बारिश और सूखा किस प्रकार झीलों के आकार को प्रभावित करते हैं। अध्ययन से पता चला कि विश्व की लगभग दो-तिहाई झीलों मौसमी परिवर्तनों के अनुसार अपनी सतह का विस्तार या संकुचन करती हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये झीलें पूरी दुनिया के झीलों के कुल भू-भाग का 66 और संख्या के लिहाज से 60 फीसद हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व की लगभग 90 फीसद जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है, जहां झीलें मौसम के अनुसार बदलती हैं।



हानिकारक ऐसों के फैलने का खतरा

वैज्ञानिकों ने बताया है कि झीलों के अतलक सिफुडने से तल में जमी गाद और तलछट सतह पर आ जाते हैं, जिससे मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का वातावरण में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यह स्थानीय जलवायु को प्रभावित करता है। झीलों की जैव विविधता खतरों में पड़ सकती है। बदलावों से झीलों की खाद्य श्रृंखला को प्रभावित होती है। शैवालों की मात्रा में असंतुलन, जलीय जीवों के आवास में बदलाव और पौधों की सरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

स्थानीय तापमान में असंतुलन का संकट

झीलों में आने वाले मौसमी उतार-चढ़ाव से जल सतक, कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव, मछली पालन में गिरावट और स्थानीय तापमान में असंतुलन जैसे संकट उत्पन्न हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने इस बात पर बल दिया है कि मौसमी बदलावों की सटीक निगरानी और समझ ही झीलों के संरक्षण, ताजे जल के संसाधनों के सुव्यवस्थित प्रबंधन और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य है। यह अध्ययन वैश्विक जलवायु नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।



सुप्रीमकोर्ट ने एनएसए के तहत हिरासत में रखे गए लॉ स्टूडेंट को रिहा करने का दिया ऑर्डर

- शीर्ष अदालत ने कहा, यह पूरी तरह अवैध, बाद में पारित किया जाएगा विस्तृत आदेश
- मध्य प्रदेश में अन्नु के खिलाफ हत्या के प्रयास व अन्य अपराधों को लेकर दर्ज की गई थी प्राथमिकी
- अन्नु की कथित तौर पर प्रोफेसर से हुई थी झड़प

NEW DELHI • PTI : उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद एहतियाती हिरासत में लिए गए एक विधि छात्र अन्नु ऊर्फ अनिकेत को तुरंत रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुश्यां और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने

के बाद पुलिस ने अन्नु पर मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता अन्नु की कथित तौर पर प्रोफेसर से झड़प हुई थी। अन्नु के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य संबंधित अपराधों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जेल में जब अन्नु था तब उसके खिलाफ एनएसए के प्रावधानों के तहत हिरासत आदेश जारी किया गया था। बाद में इस आदेश की पुष्टि की गई और तब से हर तीन महीने में इसे बढ़ाया जाता रहा है। शीर्ष अदालत की पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, 11 जुलाई, 2024 के पहले हिरासत आदेश के अवलोकन के बाद, हमने पाया है कि अपीलकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा तीन (दो) के तहत एहतियाती हिरासत में लिया गया है।





कोणार्क : सूर्य, समुद्र व संस्कृति का त्रिकोण

सूरज की पहली किरणों ने जब दिल्ली की धुंधली सुबह को चूमा, तब मैंने अपनी यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा, जो मुझे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराइयों में ले जाने वाली थी। मंजिल थी कोणार्क, ओडिशा (उड़ीसा) का वह रत्न, जहां सूर्य का रथ समय के साथ थम गया है। यह यात्रा न केवल मीलों की दूरी तय करने की थी, बल्कि इतिहास, कला और आत्मा की गहराइयों को छूने की थी। मैंने अपनी यात्रा की शुरूआत दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरकर की। सुबह की नई दिल्ली हवाई अड्डे की भागदौड़ के बीच मैंने अपने मन को शांत रखा, क्योंकि मुझे पता था कि कोणार्क की शांति मेरे इंतजार में है।

लगभग ढाई घंटे की उड़ान के बाद भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उड़ीसा की मिट्टी की सौंधी खुशबू ने मेरा स्वागत किया। वहां से कोणार्क तक की सड़क यात्रा, जो लगभग 65 किलोमीटर की थी, मैंने एक निजी टैक्सी से तय की जो कि बहुत ही मजेदार थी। हरे-भरे खेतों, छोटे-छोटे गांवों और नारियल के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि यह यात्रा केवल गंतव्य तक नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर भी एक खोज है।

कोणार्क पहुंचते ही मेरी नजर सबसे पहले सूर्य मंदिर पर पड़ी जो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित विश्व धरोहर स्थल है। यह 13वीं सदी का मंदिर, जो राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया एक विशाल रथ के रूप में खड़ा है। इसके 12 जोड़ी पहिए और सात घोड़े सूर्य देवता की गति को प्रतिबिंबित करते हैं। मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक और जीवंत है कि पथरों में प्राण बस गए हों। कामुक मूर्तियां, नृत्य करती अप्सराएं और सूर्य की किरणों के साथ बदलते रंगों का नजारा मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। मैंने सुबह की पहली किरणों के साथ मंदिर में प्रवेश किया, जब सूर्य की रोशनी मंदिर को स्वर्णिम आभा से नहला देती है।

मंदिर के परिसर में एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहां प्राचीन मूर्तियां और मंदिर के इतिहास से संबंधित जानकारी प्रदर्शित है। मैंने वहां कुछ समय बिताया, यह समझने की कोशिश की कि कैसे इस मंदिर ने समय की मार को सहते हुए भी अपनी भव्यता को बचाकर रखा है।

कोणार्क का आकर्षण केवल सूर्य मंदिर तक सीमित नहीं है। मैंने चंद्रभागा बीच का भी अवलोकन किया, जो मंदिर

युगवकड़ की पाती

जोड़ी पहिए और सात घोड़े सूर्य देवता की गति को प्रतिबिंबित करते हैं। मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक और जीवंत है कि पथरों में प्राण बस गए हों। कामुक मूर्तियां, नृत्य करती अप्सराएं और सूर्य की किरणों के साथ बदलते रंगों का नजारा मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। मैंने सुबह की पहली किरणों के साथ मंदिर में प्रवेश किया, जब सूर्य की रोशनी मंदिर को स्वर्णिम आभा से नहला देती है।



संजय शेफर्ड
नई दिल्ली



Email- thephotonnewsjharkhand@gmail.com

- हमें अपना फ्रीडबैक, सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए दिए गए बार कोड को स्कैन करें या मेल करें।
- आप हमें अपनी रचनाएं, कविता या आलेख भी भेज सकते हैं। जिसे हम अपने आने वाले अंक पर प्रकाशित करेंगे।

से कुछ ही किलोमीटर दूर है। समुद्र की लहरों का संगीत और सूर्यास्त का नजारा, आत्मा को शांति देता है। यह

समुद्रतट तीर्थयात्रियों और पर्यटकों, दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थल है। मैंने वहां कुछ समय ध्यान करते हुए



बिताया, लहरों की शोर के बीच अपने विचारों को समेटते हुए। इसके बाद, मैंने रामचंडी मंदिर की ओर रुख किया, जो कोणार्क से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर मां रामचंडी को समर्पित है

और स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। मंदिर का शांत वातावरण और नदी के किनारे का सुंदर दृश्य मन को सुकून देता है।

मन को भाते ओड़िया व्यंजन

कोणार्क में भोजन का अनुभव भी उतना ही समृद्ध है, जितना इसकी संस्कृति। मैंने स्थानीय रेस्तरां सूर्य उदय में ओड़िया थाली का आनंद लिया, जिसमें दालमा (दाल और सब्जियों का मिश्रण), बादी चुरा (तले हुए उड़द दाल के टुकड़े) और चिंगुड़ी मालाई करी (झींगा करी) शामिल थी। मिठाई के लिए, मैंने रसबली का स्वाद लिया, जो छेना से बनी एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे दूध और केसर की चाशनी में डुबोया जाता है। कोणार्क के समुद्रतट के पास कई छोटे ढाबे भी हैं, जहां ताजा मछली और समुद्री भोजन (सी-फूड) परोसा जाता है। मैंने एक स्थानीय ढाबे में भुनी हुई मछली खाई, जिसका स्वाद अभी भी मेरे जिह्वा पर बरकरार है। यदि आप शाकाहारी हैं तो कोणार्क में कई रेस्तरां जैसे कमलाबाई में शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। यहां की खिचड़ी और साग-सब्जी की थाली सादगी और स्वाद का अनूठा संगम है।

सूर्यास्त का नजारा आनंददायक

ठहरने के लिए कई विकल्प कोणार्क में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं जो हर बजट के लिए उपयुक्त हैं। मैंने लोटस इको रिसॉर्ट में रुकने का फैसला किया, जो समुद्र तट के पास स्थित है। यह रिसॉर्ट पर्यावरण के अनुकूल है और स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। कमरों से समुद्र का नजारा और सुबह की शांत हवा मन को तरोताजा कर देती है। इसके अलावा, यात्री निवास और पक्कानिवास कोणार्क जैसे सरकारी गेस्ट हाउस भी आरामदायक और किफायती हैं। यदि आप लवजरी की तलाश में हैं, तो भुवनेश्वर में मेफेयर लगून जैसे होटल एक शानदार अनुभव प्रदान करते हैं, हालांकि इसके लिए आपको कोणार्क से भुवनेश्वर की यात्रा करनी होगी। कोणार्क की मेरी यात्रा केवल स्थानों का भ्रमण नहीं था, बल्कि यह एक

आंतरिक यात्रा थी। सूर्य मंदिर की भव्यता ने मुझे कला और इतिहास की गहराई में ले जाया, चंद्रभागा बीच ने मुझे प्रकृति के साथ एकाकार होने का मौका दिया और स्थानीय भोजन ने मेरे तन-मन को तृप्त किया। कोणार्क की सड़कों पर चलते हुए मैंने स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और उनकी सादगी को महसूस किया। यह यात्रा मुझे दिल्ली की भागदौड़ से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले गई, जहां समय धीमा पड़ता है और आत्मा को सुकून मिलता है। जब मैंने वापसी की उड़ान पकड़ी तो मेरे मन में कोणार्क की यादें और सूर्य मंदिर की वह स्वर्णिम आभा बसी थी। यह यात्रा मेरे लिए एक साहित्यिक तीर्थयात्रा बन गई, जहां मैंने न केवल एक स्थान को खोजा, बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेरणा को भी पाया।

अक्टूबर से मार्च के बीच जाएं

अक्टूबर से मार्च के बीच जाएं इस जगह पर यदि आप भी आना चाहते हैं, तो यात्रा का समय अक्टूबर से मार्च तक का सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है। दिल्ली से भुवनेश्वर तक उड़ान और फिर टैक्सी या बस से कोणार्क पहुंचा जा सकता है। सूर्य मंदिर के

लिए गाइड लेना उचित है जो मंदिर की कहानियों को जीवंत कर देगा। सूर्यास्त के समय चंद्रभागा बीच जरूर जाएं और स्थानीय भोजन का स्वाद लेना न भूलें। यह यात्रा मेरे लिए एक काव्य थी जिसमें सूर्य, समुद्र और संस्कृति ने मिलकर एक अविस्मरणीय राग रचा। कोणार्क, तुम मेरे दिल में बसे हो।

पुस्तक-चर्चा

साहित्य के भीष्म पितामह : डॉ. सत्यदेव ओझा

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था 'साहित्यकार उस पीयूषवर्षी मेघ के समान होते हैं, जो ज्ञान की अमृतमयी बूंदों से पूरे समाज को आप्लावित कर जाते हैं, जिसमें समाज-कल्याण का भाव अन्तर्निहित होता है'... इन पंक्तियों ने मुझे जीवन का अनमोल मंत्र ही दे दिया था। ऐसे ही साहित्यकारों की कृतियाँ कालजयी बन, अमर हो जाती हैं-- वर्ष भर पढ़ी जाने वाली साहित्यिक पुस्तकों में एक पुस्तक ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, जिसका नाम था 'विनोबा -मैं और तुम'। लेखक थे डॉ. सत्यदेव ओझा। इस पुस्तक के विमोचन समारोह में भी शामिल हुई थी, परन्तु कभी यह नहीं सोचा था कि यह अमर कृति मुझे मिल पाएगी, लेकिन स्वयं डॉ. सत्यदेव ओझा ने सस्नेह मुझे यह पुस्तक उपहार स्वरूप दी और मुझे अपार संभावनाओं का साहित्यकार बताते हुए आशीर्वाद भी दिया। मैं चकित थी कि क्या सचमुच रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व समाहित होता है?, मैंने पढ़ना प्रारम्भ किया, तो पढ़ती चली गई -एक अद्भुत सम्मोहन, आंतरिक-आध्यात्मिक सुख की अनुभूति। सब कुछ वर्णनातीत था, विनोबा जी के साथ बिताए गए अनमोल पलों में जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों के विशद विवेचन के साथ साथ, कितने सुलझे-अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर व उनके समाधान सहज भाव से मिलते चले जाते हैं, मानों विधाता की सृष्टि के नए आयाम खुल रहे हों... जिनका माध्यम बने थे, एक पिता के द्वारा लिखे गए अपने पुत्र के नाम कुछ पत्र - आचार्य विनोबा के साथ



पूजा मिश्रा

बिताए समय के अनुभवों और गीता के आध्यात्मिक ज्ञान के कई रहस्यों को बड़े ही सरल ढंग से लिखे पत्रों में उनके छोटे पुत्र संतोष की जिज्ञासा भी है और पिता द्वारा अपने पुत्र को शिष्यवत ज्ञान की बातें समझाना भी -मैं अभिभूत थी... जहा कहीं उलझनें आतीं, वहां चित्रों के माध्यम से समाधान मिल जाता है। पंडित ज्ञानेश्वर की पंक्तियों की सुन्दर व्याख्या करते हुए लेखक ने बताया है कि वाणी की शक्ति कैसी होनी चाहिए, मन को छू जाती है, 'साँच आणि मवाल-मितले आणि रसाल'। वाणी सत्य हो, मृदुल हो, परिमित हो, रसीली हो जैसे अमृत की लहर, संदेह तोड़ने वाली हो, जैसे तीक्ष्ण लौह, फिर भी मधुर हो'।

वस्तुतः सारा कार्य-व्यापार तो वाणी का ही है, इस संसार में व्यक्ति की वाणी ही उसे कभी शिखर पर आसीन कराती है, तो कभी पददलित भी, राग, लोभ, द्वेष, मोह, प्रेम, प्रीति, घृणा... के द्वारा लिखे गए अपने पुत्र के नाम एकमात्र माध्यम भी वाणी ही है, फिर



क्यों न वाणी की मधुरता को जीवन का एक अभिन्न अंग ही बना लें ! पत्र संख्या-4 में भाई संतोष के प्रश्न का उत्तर हुए विनोबा जी के माध्यम से लेखक ने कहा है - 'जो मंद विद्यार्थी बनता है', इन पंक्तियों के माध्यम से ओझा जी ने व्याख्या की है-कि मंद विद्यार्थी अपने अध्ययन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सहज ही समझता है, अतः विद्यार्थी के मन को अच्छी तरह ज्ञान की गूढ़ बातें समझ सकता है, पंक्तियाँ नई प्रेरणा दे गईं। इसी प्रकार

पत्र संख्या 7 में वर्णित पंक्तियाँ दिग्भ्रमित मन को नई दिशा-नई राह दिखा सकती हैं, 'हमें दूसरों के गुण देखने चाहिए और गुणों के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्मन में प्रवेश करना चाहिए' - आदरणीया उपा बहन के पत्रों ने तो इस पुस्तक में चार चाँद लगा दिए हैं, विनोबा जी जैसे संत सचमुच अमृतवर्षी मेघ के समान हैं जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान के अमृत से समाज को उपकृत कर जाते हैं, पत्र संख्या 10 में पूछे गए एक प्रश्न- 'जीवन में शांति कैसे प्राप्त किया जाये?' के उत्तर में जब विनोबा

जी कहा - 'त्यागात शान्ति:' तब ओझा जी उसकी सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं- 'यह गीता मंत्र है, फल त्याग से शांति प्राप्ति होती है, अपने को कर्म से अलग करना, क्योंकि कर्म कराने वाला समाज ही है', अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ मैंने जाना-सीखा और समझा, वह ज्ञान आजीवन मेरे हृदय में रहेगा, पुस्तक संग्रहणीय एवं पठनीय है...

साहित्य के भीष्म पितामह - स्मृति शेष आदरणीय डॉ. ओझा जी को मेरा शतशः प्रणाम -नमन।

विदेक कुमार शुक्ल
आरट्यु विश्वविद्यालय
उनामार्क

विदा

तुम्हारी निशानियाँ एक एक कर के विदा लेने लगी है निम्मी
उन जाड़ों में जो दस्तानें तुमने मेरे लिए खरीदे थे
उनकी सिलाई अब उधड़ने लगी है
उनकी गरमाई अब विदा होने लगी है
हमारे प्रेम की निशानियों की तरह
तुम्हारा दिया झोला अब बूढ़ा हो गया है
और सुस्ता रहा है मेरे घर के तहखाने में फेसबुक स्मृति में
अब नहीं दिखती हमारी तस्वीरें
तुम्हारे नाम लिखे मेरे संदेश
तुम्हें भेजे चुम्बन
हमने कभी दुनिया को बताया था कि हम प्रेम में हैं
वो निशानियाँ गायब होने लगी है
तुम्हारे शरीर के तिलों की तरह निम्मी हमें मिलना चाहिए एक बार
उन निशानियों को विदा कहने जो अब तक साथ थी हमारे कि भटकती है जो प्रेतों की तरह अंत्येष्टि की प्रतीक्षा में

समाचार सार

मां विपदतारिणी को पूज मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला में शनिवार को धूमधाम से मां विपदतारिणी की पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा के विपदतारिणी रूप के आगे माथा टेककर अपने परिवार की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। महिलाओं

ने एक-दूसरे की मांग में सिंदूर भर कर सदा सुहागन बने रहने की कामना की। पुजारियों ने भी श्रद्धालु महिलाओं की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर हर विपदा से दूर रहने का आशीर्वाद दिया। पूजा का आयोजन चाईबासा सदर बाजार के श्रीश्री काली मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई। मां की पूजा हर साल जगन्नाथ रथयात्रा के प्रारंभ और बाहुड़ा यात्रा के बीच शनिवार व मंगलवार को की जाती है। पूजा का आयोजन काली मंदिर में सेवारत राय परिवार द्वारा किया गया। पूजा मुख्य पुरोहित दिव्येन्दु राय तथा सहयोगी परिमल गांगुली, अनूप मुखर्जी, नाडु गोपाल राय आदि ने संपन्न कराई। पूजा में 13 किस्म की सामग्री अर्पित की गई। भोग में पुड़ी, पुआ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मूंगदाल, फल, खीर, मिष्ठान , चेरी आदि का भोग लगाया गया।

होमगार्ड व अग्निवीर के लिए चल रही प्रैक्टिस

CHAKRADHARPUR : कोल्हान नितिर तुरतुंग (केएनटी), चक्रधरपुर शाखा के अधीनस्थ सिलफोड़ी के शांतिनगर मैदान में 15 दिनों से होमगार्ड और अग्निवीर सेना में भर्ती के लिए प्रैक्टिस चल रही है। इसमें शनिवार को फिजिकल टेस्ट लिया गया।

इस दौरान दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और शटपुट लिया गया, जिसमें 68 पुरुष और 37 महिला प्रशिक्षु शामिल हैं। पूर्व सैनिक दयासागर केराई के मार्गदर्शन में चल रहे प्रशिक्षण में संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व सैनिक माझीराम जामुदा, महासचिव प्रेमसिंह डांगिल, कार्यालय सचिव एवं एथलेटिक संघ के समन्वयक हेमंत सामड, सक्रिय सदस्य रबिन्द्र गिलुवा व पूर्व सैनिक राम बोदरा भी उपस्थित रहे।

विधायक सरयू राय ने बांटे 113 पेंशन प्रमाणपत्र

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने शनिवार को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 111 और विधवा सम्मान पेंशन योजना के दो समेत 113 लाभुकों को प्रमाणपत्र दिए। इनमें कदमा, सोनारी, साकची और

बिष्टपुर क्षेत्र के पेंशनधारक शामिल थे। दिव्यांग प्रमाणपत्र लाभुकों के आवास पर भेज दिया जाएगा।

चक्रधरपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में बिजली विभाग द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शनिवार से शुरू कर दिया गया है। इसमें सभी पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागाए जाएंगे। पहला मीटर चक्रधरपुर के पवन चौक

स्थित छप्पन भोग मिठाई की दुकान में लगाया गया है। इस दौरान विभाग के एसडीओ भामा टुडू भी मौजूद थे। भामा टुडू ने बताया कि इस मीटर में सिम लगा हुआ है। आपको जितनी बिजली का उपभोग करना है, उतना रिचार्ज कीजिए। इससे बिल बकाये की समस्या नहीं होगी। इस मौके पर जेई अजय हंस, बेनटेक कंपनी के इंचार्ज पीयूष तिवारी व संजय यादव भी थे।

इंटर की पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार विफल : भाजपा

JAMSHEDPUR : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने शनिवार को जमशेदपुर महानगर के साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह अराजकता की स्थिति में पहुंच गई है। राज्य सरकार की घोर उदासीनता और कुप्रबंधन के कारण आज प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। डॉ. गोस्वामी ने कहा कि वर्ष 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत देश भर में डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को अलग करने का निर्देश दिया गया था। इस नीति के तहत राज्यों को स्कूलों को अपग्रेड कर इंटर की पढ़ाई की अलग व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। विभिन्न राज्यों ने यह कार्य समय रहते कर भी लिया, लेकिन हेमंत सरकार ने पिछले साढ़े पांच वर्षों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं किया एवं शिक्षकों की बहाली में भी रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में पास हुए चार लाख से अधिक विद्यार्थी फर्स्ट इंयर एडमिशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। डिग्री कॉलेजों ने इंटरमीडिएट के दाखिले बंद कर दिए हैं, परंतु राज्य सरकार यह स्पष्ट करने में असमर्थ है कि इन विद्यार्थियों का एडमिशन कहाँ और कैसे होगा। सरकार के पास न तो पर्याप्त विद्यालय हैं, न शिक्षक, और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी कक्षाएं या प्रयोगशालाएं।

हत्या के 5 साल बाद पुलिस ने किया मामले का खुलासा, तीन गिरफ्तार, दो हुए फरार

प्रेम प्रसंग में युवक की हुई थी हत्या, जंगल में दफना दिया था शव, कंकाल हुआ बरामद

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में 2020 में हुए सीताराम बोदरा हत्याकांड का 5 साल बाद खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राम बोदरा, पातोर होनहागा और लालो बोदरा शामिल हैं। टैटैईपदा गांव निवासी सीताराम बोदरा लापता हो गया था। उसके भाई नंदू बोदरा ने अपने भाई के अपहरण और हत्या की आशंका जमाते हुए 20 सितंबर 2020 को मामला दर्ज कराया था। लेकिन, पुलिस को सफलता नहीं मिली थी। इसी दौरान 27 जून को इस कांड में शामिल एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो पूरे मामले का उद्घेदन हो गया। इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को और गिरफ्तार

किया, जबकि इस हत्याकांड के दो आरोपी अब भी फरार हैं।

सीताराम बोदरा का माधे दिग्गी नामक महिला से प्रेम प्रसंग था, जिसे पातोर होनहागा और माधे दिग्गी के परिवार वाले स्वीकार नहीं करते थे। इसी कारण इन लोगों ने सीताराम बोदरा की हत्या कर दी थी।

टैटैईपदा गांव निवासी पातोर होनहागा, माधे दिग्गी और लाल बोदरा उर्फ गोरम बोदरा, राम बोदरा, लाण्डूपोदा निवासी विशाल पूर्ति ने सीताराम बोदरा को जान से मार कर रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा था। इसके बाद सभी ने अपहरण कर उसकी हत्या की और शव को दफना दिया था।

वाहन की चपेट में आकर व्यक्ति की हुई मौत, मृतक की पहचान में जुटी पुलिस

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव में रात्री-चाईबासा मुख्य मार्ग एनएच-75ई पर किसी वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बदगांव थाना प्रभारी दुर्गा शंकर मंडल ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वे घटनास्थल पहुंचे और शव को बरामद किया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल के शीतगृह में रखा गया है। जानकारी के अनुसार, बदगांव थाना अंतर्गत जलमय गांव के समीप यह दुर्घटना हुई है। मृतक के शरीर पर हल्के पीले रंग की फुल शर्ट और ब्लू रंग की पैंट है। पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील की है कि अगर किसी को मृतक के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे थाने में संपर्क करें।

साकची स्थित अग्रसेन भवन में जयकारा लगाते आयोजक

JAMSHEDPUR : सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से इस वर्ष भी नि:शुल्क कांवर यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को साकची स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि 25 जुलाई को 1000 शिवभक्तों का जत्था कांवर यात्रा के लिए जमशेदपुर से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। पंजीयन प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू होगी और यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के लोग ही यात्रा के लिए पंजीयन कर सकेंगे। सभी पंजीकृत यात्रियों को फोटो और मोबाइल नंबर सहित पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिससे हर जगह प्रवेश सुनिश्चित होगा। विकास सिंह ने बताया कि कांवरियों की पहचान के लिए विशेष ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान कोई भी कांवरिया अपने जत्थे से बिछड़े नहीं। यात्रा में सोनारी, कदमा, बिष्टपुर, साकची और मानगो के भक्त शामिल होंगे। ठहराव स्थलों को आरक्षित कर लिया गया है।

मकान ढहने से बुजुर्ग महिला सहित तीन हुए घायल, अस्पताल में भर्ती

PHOTON NEWS JSR : सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के निर्मल नगर में शनिवार सुबह एक हादसा हो गया। लगातार बारिश के कारण एक कच्चा मकान और छप्पर ढह गया। इस दुर्घटना में बुजुर्ग महिला सहित तीन लोग घायल हो गए हैं। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार बारिश के कारण सीतारामडेरा थाना क्षेत्र स्थित निर्मल नगर (हुयूम पाइप निर्माण नगर) में शनिवार की सुबह एक कच्चा मकान और छप्पर अचानक ढह गया। हादसे के वक्त घर के अंदर सो रहे परिवार के तीन सदस्य मलबे में दब गए। चिख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। घायलों में 82 वर्षीय



घायल युवक

बुजुर्ग महिला रेणुका दास, उनका बड़ा बेटा विनोद दास (47) और छोटा बेटा पविर दास (40) शामिल हैं। हादसे में रेणुका दास का हाथ और पैर टूट

गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों घायलों को टेंपो से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। घायल के चचेरे भाई उज्जवल दास ने बताया कि रेणुका दास के पति का निधन हो चुका है। दोनों बेटे मजदूरी कर किसी तरह अपने और अपनी बुजुर्ग मां का पालन-पोषण करते हैं। रेणुका दास को वृद्धा पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। परिवार बरसों से मिट्टी और खपड़े के जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। लगातार बारिश से दीवारें कमजोर हो गई थीं और बांस-रोला सड़ जाने के कारण शनिवार सुबह पूरा मकान ढह गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से परिवार की मदद की मांग की है।

अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने राजविवजयपुर और बेनटांगर के बीच सुनसान कैनाल के किनारे से खोदाई कर मृतक का कंकाल बरामद किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हत्या में शामिल दो अन्य आरोपियों (महिला माधे दिग्गी और विशाल पूर्ति) फरार हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चला रही है। पोड़ाहाट के पुलिस अधिकारी शिवम प्रकाश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा किया। इस मौके पर कराईकेला के थाना प्रभारी अंकित कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक गौतम कुमार, चंदन शुभम शर्मा के अलावा कराईकेला थाना के जवान उपस्थित थे।

मकान बनाने के लिए खोदा था गड्ढा दो सगे भाइयों की डूबकर हो गई मौत जमे हुए पानी में खेलते समय पैर फिसलने से गिरे

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुख्यालय चाईबासा में दो सगे भाई, विशाल और विकास, घर के सामने खोदे गए एक गड्ढे में खेलते समय डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की है। घर के सामने खोदे गए एक गड्ढे में दोनों भाई पानी से खेल रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। घर वाले दोनों बच्चों को लेकर चाईबासा के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। मुफरिसल थाना क्षेत्र के रगुड़पंचो गांव निवासी पलटन सिंह कुटिया के दोनों पुत्र

मुफरिसल थाना क्षेत्र के रगुड़पंचो गांव निवासी पलटन सिंह कुटिया ने घर के सामने ही घर बनाने के लिए मिट्टी के लिए गड्ढे खोदे थे। लेकिन, बरसात का पानी भर जाने से घर बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे ने ही घर का विरग बुझा दिया।

विकास सिंह कुटिया (7वर्ष) और विशाल सिंह कुटिया (5 वर्ष) शुक्रवार को दोनों बच्चे पानी से भर एक गड्ढे के सामने खेल रहे थे। वहां दोनों का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। दोनों बच्चों को डुबता देख कर आसपास खेल रहे अन्य बच्चों ने शोर मचाया। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला। इलाज के लिए दोनों बच्चों को नजदीक के चाईबासा स्थित सदर अस्पताल पर ले जाया गया।

मुसाबनी में पुनर्वासित किए जाएंगे चाटीकोचा गांव के लोग

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएससी) के सोनारी स्थित डिपो में पर्याप्त मजदूर नहीं रहते। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने शनिवार को सोनारी स्थित जेएनएससी (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति) के अस्थायी डिपो का शनिवार को आंचक निरीक्षण किया, तो डिपो में कई समस्याएं दिखाई दीं। यह निरीक्षण स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद किया गया। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी खामी यह देखने को मिली कि डिपो में मजदूरों की हाजिरी रजिस्टर ही मौजूद नहीं था। यह स्पष्ट नहीं था कि कौन-कौन से मजदूर किस क्षेत्र में काम पर जा रहे हैं। विधायक को मजदूरों ने मुश्की के व्यवहार को लेकर भी शिकायत दी और कहा कि उसका रवैया बेहद अपमानजनक और मनमाना है। विधायक ने बताया कि सुबह 8:30 बजे तक वहां केवल 22 मजदूर उपस्थित थे, जबकि नियम के अनुसार 50 मजदूरों को उपस्थित रहना चाहिए था। पूछे जाने पर मुश्की कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। विधायक को जानकारी मिली थी कि जेएनएससी की ओर से इस डिपो की निगरानी के लिए कुल पांच सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं।

सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यक सामाजिक एवं सामुदायिक ढांचे को भी विकसित किया जाए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि यांत्रिकी विभाग प्रोजेक्ट का प्रारूप एवं प्राक्कलन तैयार करें, जिसमें विस्थापित परिवारों की मूल भूतल आवश्यकताओं के साथ-साथ स्थानीय सामाजिक भावनाओं का भी समुचित ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन एवं यूसीआईएल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की जायज मांगों, जरूरतों एलिंग पॉन्ड से त्रस्त इन परिवारों को मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत बेनाशोल के चिह्नित स्थान पर पुनर्वासित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि पुनर्वास स्थल पर भूखंड, आवास, बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत

राष्ट्रीय भाव के जागरण में साहित्यकारों की भूमिका पर कराई गई परिचर्चा

JAMSHEDPUR : सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन व तुलसी भवन संस्थान द्वारा डेढ़ माह तक चलने वाले 'तुलसी जयंती समारोह' के अंतर्गत शनिवार को शाम 4 बजे से संस्थान के प्रयाग कक्ष में साहित्यकारों के लिए साहित्यिक परिचर्चा की गई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भाव के जागरण में साहित्यकारों की भूमिका विषय पर साहित्यकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मृतका तथा संचालन साहित्य समिति के सचिव डॉ. अजय कुमार ओझा ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्थान के कोषाध्यक्ष मिलल कुमार जालान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आरंभ में स्वागत वक्तव्य तथा विषय प्रवेश संस्थान के मानद महासचिव डॉ. प्रसन्नजित तिवारी तथा धन्यावाद ज्ञापन समिति के दिवेंद्र त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के वित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण कर किया गया।

ओवरलोड होते ही बिजली विभाग को मिल जाएगी जानकारी, बढ़ा दी जाएगी क्षमता

अब नहीं जलेंगे बिजली के ट्रांसफॉर्मर, लगाया जा रहा डिजिटल मीटर

● दो साल में पूरी हो जाएगी उपकरण लगाने की प्रक्रिया

MUJTABA RIZVI @ JSR : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जमशेदपुर सर्किल में अब बिजली विभाग ऐसा इंतजाम कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मर का जलना मुश्किल बात हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मर नहीं जलेंगे और इस वजह से उपभोक्ताओं को होने वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसके लिए बिजली विभाग सर्किल के सभी ट्रांसफॉर्मरों में डीटीआर यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर लगा रहा है। यह मीटर जमशेदपुर सर्किल के मानगो, जमशेदपुर, घाटशिला और आदित्यपुर इलाके में लगाए जा रहे हैं।



प्रतीकात्मक तस्वीर

2158 ट्रांसफॉर्मरों में लगेंगे डिजिटल मीटर जमशेदपुर सर्किल में मानगो, जमशेदपुर, घाटशिला और आदित्यपुर इलाके आते हैं। इन इलाकों में अभी 2158 ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। यह सभी ट्रांसफॉर्मर दो लाख 15 हजार 873 केवीए लोड के हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर लग जाने के बाद पता चलेगा कि आखिर इन ट्रांसफॉर्मरों पर वास्तव में क्या लोड है। अगर लोड बढ़ेगा तो कम क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर हटा कर उनकी जगह अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे।

कम लोड दिखाने से होती है समस्या

डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर ट्रांसफॉर्मरों के लोड बताएगा। मीटर यह बताएगा कि किस ट्रांसफॉर्मर में कितना लोड है। अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में लोड बढ़ जाएगा तो उस ट्रांसफॉर्मर को विभाग हटा कर वहां अधिक क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लगा देगा। इस तरह, अधिक लोड से ट्रांसफॉर्मर नहीं जलेगा। अभी अधिकतर ट्रांसफॉर्मर लोड बढ़ने की वजह से जल जाते हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई उपभोक्ता लोड कम दिखा कर कनेक्शन लेते हैं जबकि, उनके घर में अधिक लोड बिजली की खपत होती है। मगर, अब यह मीटर ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड को बताएगा, जिससे बिजली विभाग को स्थिति समझने में आसानी होगी। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मर 100 केवीए का है और उस पर 150 केवीए का लोड पड़ रहा है। तो उस ट्रांसफॉर्मर को हटा कर वहां 200 केवीए का ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जाएगा।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। सिव्थोर कंपनी यह काम देख रही है। दो साल के अंदर जमशेदपुर सर्किल के सभी ट्रांसफॉर्मरों में यह डिस्टिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मीटर लगा दिया जाएगा।

सुधीर कुमार
अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर सर्किल

विभाग ने एजेंसी को जल्द लगाने के लिए निर्देश

जमशेदपुर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। यह काम तेजी से चल रहा है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि मानगो, घाटशिला, जमशेदपुर और आदित्यपुर में सभी ट्रांसफॉर्मरों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर लगाने का काम दो साल में पूरा कर लिया जाएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर लगाने का काम सिव्थोर कंपनी कर रही है। कंपनी को हिदायत दी गई है कि वह यह काम तेजी से करे ताकि समय सीमा के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मर मीटर लगाने का काम पूरा किया जा सके।

एससीओ में रक्षामंत्री का चीन-पाक को कड़ा संदेश



निश्चित ही एससीओ सम्मेलन में भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एक निडर एवं साहसिक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने की भारत की नई नीति की रूपरेखा सम्मेलन में रखी। उनका कहना था कि संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद जैसी सामूहिक सुरक्षा से उत्पन्न चुनौती के मुकाबले के लिये एकजुट होना चाहिए। उनका मानना था कि कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद दुनिया में शांति, सुरक्षा और विश्वास को कम कर रहे हैं। यह भी कि आतंकवाद पर तार्किक प्रहार किए बिना सदस्य देशों में शांति व समृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने उन तत्वों को बेनकाब करने का प्रयास किया जो आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिये उसे प्रश्रय देते हैं। उनका मानना था कि एससीओ आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने के बजाय इसको प्रश्रय देने वाले देशों की आलोचना करें, आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम में निष्पक्ष बने। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षामंत्री इस पर भी अड़े रहे कि एससीओ में आतंक का समर्थन करने वाले देशों की निंदा एवं बर्त्सना होनी चाहिए। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान को बख्शा न जाए, लेकिन चीन ने आशंका के अनुरूप ढिठाई एवं बदनियत ही दिखाई। चीन लगातार पाक के आतंकवाद पर सहयोगी दृष्टिकोण अपनाये हुए है। उसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त होना चाहिए लेकिन वह पहले भी आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह पाक के आतंकी सरगनाओं का बचाव कर चुका है। इससे उसकी बदनामी

दरअसल, एससीओ सम्मेलन में भारत चाहता था कि अंतिम दस्तावेज में आतंकवाद को लेकर भारतीय चिंताओं को जगह दी जाए। इसीलिये सम्मेलन में रक्षामंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की तार्किकता को बताया और पहलगाम आतंकी हमले के सदाबहार दोस्त चीन को दबदबे वाले घटना दुनिया के सामने स्पष्ट थी और दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा भी की। इसी से दो देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई, एससीओ सम्मेलन में उस हमले को तवज्जो न देने की रणनीति दरअसल हकीकत के साथ मखौल एवं दौंगलापन है। लेकिन सम्मेलन में रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी-7 शिखर सम्मेलन में कही उन बातों को ही विस्तार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंक के अपराधियों और इसके पीड़ितों को एक तराजू में कैसे तोला जा सकता है? यह कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया था।

पाक और उसके करीबी सहयोगियों के नापाक इरादों को दुनिया को बताने तथा भारत की बात हर देश तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहु-पक्षीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे। लेकिन पाक के सदाबहार दोस्त चीन को दबदबे वाले एससीओ सम्मेलन में पाक के आतंकी मनसूबों को लेकर स्पष्ट नजरिया बनना जरूरी है। एससीओ की घोषणा में अगर यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तान की गड़बड़ी में भारत शामिल है, तो फिर भारत को ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। ऐसे झूठे एवं भ्रामक तथ्यों का प्रतिकार जरूरी है। ऐसे झूठ को फैलाकर ही पाक दुनिया से सहानुभूमि जुटाता रहा है। इसलिये किसी भी ऐसे विषय स्तरीय सम्मेलन में अपनी बात भी पुरजोर ढंग से तथ्यपरक तरीके से रखनी चाहिए। वहां पारित होने वाले प्रस्तावों के प्रति रक्षामंत्री की भांति ज्यादा संवेदनशील एवं सख्त होने की जरूरत है। भारत अपनी इसी नीति को दोहरा कर शत्रु मानसिकता वाले देशों को सबक दे सकेगा। पाक के प्रति भारत की सख्ती हर मोर्चे पर दिखाई दे। भले ही पाक हकीकत न देखने की गलती दोहराता रहे। अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित तथा प्रयोग करने वालों के विरोध परिणाम भुगतने ही होंगे। ऐसा करते हुए वह कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है, वह लगातार गरीबी और कमजोरी का शिकार हो रहा है। आतंकवाद को पोषित करते हुए यह देश अन्य देशों की दया पर आश्रित होता जा रहा है। लेकिन भीख में मिली दया या अनुदान से कब तक खुद को कायम रख पायेगा?

संपादकीय

पाकिस्तान फिर बेनकाब

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब करते हुए भारत पर ही आरोप मढ़ने की उसकी चाल को विफल कर डाला। आतंकवाद के खिलाफ अपने कड़े रुख पर कायम रहते हुए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करने और सीमा पार से होने वाले पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के प्रति भारत कीचिंतों को अनदेखा करने पर बृहस्पतिवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथसिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को वक्तव्य में शामिल करने की मांग की, जबकि पाकिस्तानी पक्ष ने बलूचिस्तान में चरमपंथी गतिविधियों पर टिप्पणी डलवाने पर जोर दिया, जो साफ-साफ भारत पर आरोप मढ़ने का प्रयास था। पाकिस्तान की इस हरकत के कारण सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य के बिना ही समाप्त हो गया। वक्तव्य के मसौदे में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं था और न ही सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भारत के रणनीति को दृष्टांत दिया था। ये सारी चालें सम्मेलन के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत के रुख को कमजोर करने के लिए चली जा रही थी, मामले को भांपते ही रक्षामंत्री ने पाक के धुरें उड़ा दिए। राजनाथ ने आतंकवाद का प्रायोजक ठहराते हुए जवाबदेह ठहराने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड रखने वालों के खिलाफ एससीओ को भी भारत जैसी कड़ी नीति अपनानी चाहिए। अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने संकीर्ण और निहित उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों को परिणाम भुगतने ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसकी शुरुआत थी जिसके तहत भारत ने आतंकवाद से बचाव तथा सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। ऑपरेशन से आतंकवाद को कड़ाई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति उसकी कार्रवाइयों के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। भारत के इन प्रयासों को एससीओ के सदस्य देशों से निःसंकोच भरपूर सहयोग और समर्थन मिलना ही चाहिए। दुनिया के इस भूभाग में इसी से शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा संगठन का उद्देश्य सार्थक हो सकेगा।

चितन-मन

जीवन में दर्द अस्थायी होता है

एक राजा ने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया और कहा, 'मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर से स्थिर बना रहूँ। जीवन के उतार-चढ़ाव मेरा संतुलन बिगाड़ देते हैं। तुम कोई ऐसी चीज बताओ जिससे दुख की अवस्था से गुजरते हुए मैं खुशी पा सकूँ और जब मैं आनंद की अवस्था में होऊँ, तो वह चीज मुझे दुखों की याद दिलाती रहे। ऐसी चीज खोजो जो मैं अपने पास रख सकूँ ताकि मेरे चारों ओर कुछ भी घटता रहे, पर मैं शांत-स्थिर रह सकूँ। सभी सलाहकार मिलकर बैठे और उन्होंने विचार-विमर्श किया। अंत में वे एक बक्सा लेकर राजा के पास गए- महाराज, आप इस बक्से को खोलें। राजा ने उसे खोला तो उसमें एक छोटी अंगूठी मिली। उन्होंने राजा से कहा, इस पर जो लिखा है, उसे पढ़ें। अंगूठी पर लिखा था- यह समय भी बीत जाएगा। इन पांच सादे लफ्जों से राजा को बड़ी मदद मिली। हमें भी संतुलन बनाए रखने में इनसे मदद मिल सकती है। जब हम बहुत आनंद में हों, तब याद रखने की जरूरत है कि चीजें हर समय ऐसी नहीं रहेंगी और जब खुशहाल वक्त गुजर जाए तो हमें निराशा या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें ये पांच सादे लफ्ज याद दिला सकते हैं कि दर्द अस्थायी है और खुशहाली फिर लौट आएगी। सभी जीवन में उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं। ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनसे बचा नहीं जा सकता। प्रश्न यह है कि जीवन-पथ पर जब हम ऊंच-नीच का सामना करेंगे तो क्या हम मन की शांति खोकर अस्थिर हो जाना चाहेंगे? अगर हम खुद को जिंदगी में घटने वाली हर घटना से प्रभावित होने देंगे तो हम आनंद की ऊंचाइयों से घोर निराशा की गहराइयों में पहुंच जाएंगे लेकिन आले ही क्षण वापस आनंद की अवस्था में होंगे। इस लगातार बदलाव से अक्सर भय, तनाव और आतंक पैदा होता है क्योंकि हमें कभी यह पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। समय के साथ, भय और तनाव की यह अवस्था हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और हम शांत या तनाव रहित नहीं हो पाते।...

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद 'मेक ईरान ग्रेट अगेन' ये वाक्य दिया था। दरअसल अमेरिका ऐसा कह कर ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना तलाश रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 'सत्ता परिवर्तन शब्द का उपयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है लेकिन अगर वर्तमान शासन ईरान को फिर से महान बनाने में समर्थ नहीं है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा?' अमेरिका ने ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई को सत्ता से हटाने की कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश की है लेकिन मुस्लिम शिया धर्म के सुप्रीम लीडर खामेनेई को हटाना संभव नहीं हो सका। इस वक्त भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की माँग उठ रही है। खुद खामेनेई के परिवार से इसकी माँग उठने लगी है। महमूद मोरदखानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के भतीजे हैं। वह 1986 में ईरान छोड़कर फ्रांस चले गए थे और निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। महमूद मोरदखानी ने कहा है कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं हैं लेकिन ईरानी सरकार का खाल्ता ही यहाँ स्थायी शांति के लिए जरूरी है। महमूद मोरदखानी के अनुसार हज़ोजी भी इस शासन को मिटा सके, वह जरूरी है हब्र उनका मानना है कि कई ईरानी लोग खामेनेई के कमजोर होने से ईरान में खुश हैं। ईरान के पूर्व शहजादे रजा पहलवी ने भी शासन में बदलाव पर जोर दिया है। उनका कहना है कि तेहरान में सत्ता पतन जरूरी है। रजा पहलवी ईरान के अंतिम पहलवी शासक मोहम्मद शाह पहलवी के बड़े बेटे हैं। उनका परिवार अमेरिका में निर्वासन की जिंदगी गुजार रहा है। 1979 में देश छोड़कर भागे पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी इस वक्त काफी सक्रिय हैं। रजा अमेरिका में रहते हैं और खुद को ईरान के शासक के रूप में देखना चाहते हैं। 2016 में पहली बार जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो शाह ने



ईरान में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने और लोकतंत्र की बहाली की वकालत की थी। इसके बाद फिर जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो पहलवी ने ईरान में लोकतंत्र की वकालत करते हुए पश्चिमी राष्ट्रों से उसके संबंध सुधारने पर जोर दिया था। अब जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो वह इजरायल का पक्ष लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईरान में अभी कई ऐसे लोग हैं जो इजरायल की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और खामेनेई को सत्ताच्युत करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन में रजा पहलवी को समर्थन दे सकते हैं और ईरान में लोकतंत्र की स्थापना की पहल कर सकते हैं। हालाँकि खामेनेई ने अपने विकल्प के तौर पर तीन उत्तराधिकारियों को चुन लिया

बताया जा रहा है। ये तीनों ही मौलवी हैं यानी ईरान को इस्लामिक राष्ट्र बनाए रखने की व्यवस्था खामेनेई ने कर दी है। ईरान में अभी कई संगठन एक्टिव हैं जो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। इनमें पीपुल्स मुजाहिदीन या मोजाहिदीन ए खल्क यानी एमईके, ग्रीन मुवमेंट प्रमुख हैं। एमईके ऐसा संगठन है जिसे गौरिल्ला युद्ध लड़ने में महारत हासिल है लेकिन अमेरिका इसे नहीं पसंद करता क्योंकि ये संगठन रूस के नजदीक रहा है। अमेरिका विरोध के बावजूद खामेनेई को उखाड़ फेंकने की कोशिश में ये संगठन लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार खामेनेई ने ही इस संगठन को कुचला था। धीरे-धीरे खुद को खड़ा करने के दौरान संगठन अमेरिका के संपर्क में भी आ गया। इस दल के नेता को अल्बानिया

में स्थापित करने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई हालाँकि आज की तारीख में ये कहना काफी मुश्किल है कि संगठन ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। ग्रीन मुवमेंट ईरान में 2009 में सुर्खियों में आया। राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए संगठन ने आंदोलन चलाया। देश में लोकतांत्रिक सुधारों की बात करने वाला ये संगठन खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहता है और अक्सर विरोध प्रदर्शन करता रहता है। इस संगठन ने 2010 में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। इस्लामिक राष्ट्र का विरोध करने के कारण इसके आंदोलन को दबा दिया गया और इसके नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आज की परिस्थिति में ये उम्मीद करना मुश्किल है कि ये संगठन ईरान में इस्लामिक सत्ता को हटा सकता है। ईरान में इस्लामिक शासन के दौरान वर्षों से महिलाओं का दमन किया जाता रहा है। हिजाब के खिलाफ महिलाएँ सड़कों पर उतरती रही हैं और सर्रेआम इसे उतार कर फेंकती रही हैं। विरोध प्रदर्शन में हिजाब जलाना, खामेनेई की तस्वीर जलाकर 'मुल्ला भाग जाओ' का नारा बुलंद करना आम रहा है। अब इन महिलाओं को खामेनेई को सत्ता से हटाने का विकल्प सामने दिखने लगा है। इधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान में सत्ता परिवर्तन पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। वे सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते। अमेरिका और इजरायल के अलावा भी कई देश हैं जो खामेनेई को सत्ता से बेदखल होते हुए देखना चाहते हैं। इनमें इराक, सऊदी अरब, लेबनान, मिस्र जैसे पड़ोसी इस्लामिक देश भी शामिल हैं। दरअसल इन राष्ट्रों का झगड़ा शिया-सुन्नी को लेकर है। ईरान एकमात्र शिया इस्लामिक देश है जबकि बाकी देश सुन्नी इस्लामिक राष्ट्र हैं।

रामस्वरूप रावतसरे

मुद्दा : समय पर न्याय मिलना जरूरी

अपनी कार्य संस्कृति को बदलने को तैयार है और यह बदलाव केवल अदालतों के भीतर नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैलना चाहिए, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या अदालतों के कार्य दिवस बढ़ा देने पर से समस्या हल हो जाएगी? जवाब है नहीं। जब तक समाज, सरकार, मीडिया, पुलिस, प्रशासन और आम नागरिक सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक अदालतों पर बढ़ता बोझ कम नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि आम आदमी खुद यह सोचे कि क्या हर विवाद अदालत तक ले जाना जरूरी है? अक्सर मामूली झगड़े जैसे कि जमीन के छोटे विवाद, पारिवारिक तनाव, लेन-देन की छोटी बातें भी कोर्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिन्हें बातचीत, पंचायत, मीडिएशन या लोक अदालत के जरिये सुलझाया जा सकता है। आम जनता को समझना होगा कि हर मामला न्यायालय में ले जाना ही समाधान नहीं, कई बार यह समस्या को और उलझा देता है। वकीलों की भूमिका भी कम अहम नहीं है। वे मुकदमे की दिशा तय करते हैं, मुकदमा लड़ा जाए या सुलझाया जाए। अगर वे केवल जीत-हार की सोच से ऊपर उठकर न्याय दिलाने की भावना से काम करें, तो लाखों मामले अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझ सकते हैं। साथ ही, यह भी जरूरी है कि वकील फर्जी या दुर्भावनापूर्ण मामलों को दर्ज करने से परहेज करें और मुबत्किल को वास्तविक कानूनी रास्ता दिखाएं। इसी तरह पुलिस और जांच एजेंसियों की भी सीधी भूमिका है। जब समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होती, जब

जांच अधूरी रहती है, जब गवाहों की सुरक्षा नहीं होती, तब मामला खिंचता चला जाता है। न्याय प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जब जांच समयबद्ध, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से मजबूत हो। कई मामलों में पुलिस की लापरवाही ही न्याय में देरी की सबसे बड़ी वजह बनती है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना होगा। जब भूमि विवाद, जल प्रमाण पत्र, किराएदारी या राजस्व से जुड़े मामूली मसले प्रशासन द्वारा समय पर न सुलझाए जाएं, तो जनता के पास अदालत जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ऐसे में तहसीलदार, एसडीएम और अन्य अधिकारी अपने स्तर पर सक्रिय रहेंगे तो कोर्ट का बहुत सारा भार हल्का किया जा सकता है। वहीं मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, उसे भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर देखा गया है कि मीडिया कुछ मामलों को इस तरह से उछाल देता है कि वह हटायल बाय मीडियाह बन जाता है। इससे न केवल न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि जनता का भ्रम भी बढ़ता है। मीडिया का काम है जनता को न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना, कोर्ट के फैसलों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना और जन-जागरूकता फैलाना है। यदि मीडिया सकारात्मक भूमिका निभाए, तो न्यायपालिका और समाज के बीच की दूरी को पाटने का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। और अंत में, सरकार और नीति-निर्माताओं की भूमिका इस पूरी तस्वीर में केंद्रीय है। यदि जजों की संख्या पर्याप्त नहीं



होगी, यदि अदालतों की इमारतें खस्ताहाल रहेंगी, यदि कोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो किन्तने भी कार्य दिवस क्यों न बढ़ा दिए जाएं, नतीजे नहीं आएंगे। सरकार को न्यायिक बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ई-कोर्ट जैसी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए और न्यायिक नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ निपटना चाहिए।

J P Nadda: BJP president with nine lives

As the world’s largest political party contesting serial elections, notching more hits than misses and running governments at the Centre and 14 states, the BJP is known to be a stickler for organisational propriety and discipline. It’s no mean achievement considering that the exercise of executive and legislative power alters the dynamics within a party for the worse.

In the long years when the BJP was in the opposition, it scrupulously adhered to its own Constitution—as distinct from the Indian Constitution—particularly when confronted with imbroglíos involving the leadership. The veto power lay with the extended family’s head, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, that had the last word and sometimes shot down the BJP’s proposals and decisions to party leaders’ discomfiture. The RSS’s assertions were manifest after the BJP was seated at the Centre and some states. Competing pulls and pressures became inevitable as the playing field grew larger and the stakes for BJP leaders bidding for absolute power became apparent.In 1991, when L K Advani became the opposition leader in the Lok Sabha, without a fuss he relinquished the BJP presidency for Murli Manohar Joshi. The import of this act gets amplified when in 2005, he scripted encomiums for Muhammad Ali Jinnah during a visit to Jinnah’s mausoleum in Karachi.

Following the first outcry of protest from Gujarat, where Prime Minister Narendra Modi was the chief minister and in the thick of fighting local body polls, Advani was pressured by the BJP and RSS’s sarsanghchalak K S Sudarshan to quit office as the BJP chief. But ringed by a cabal of new friends and advisers who advocated the merits of converting to secularism, Advani fought back for a while and eventually gave up office. If the BJP and Advani had still not become the forces they were by then despite the BJP losing the 2004 election, the view was he would have acquiesced.

Notwithstanding the skirmishes in BJP-ruled states—most notably between two factions in Gujarat, of which one was aided by Modi, then a state general secretary—the party made it a point to hold organisational polls from the lowest tier every three years. Rivalries often surfaced at the mandal and district tiers, but these were quelled to allow the process of appointing a new president to go on. So far in its history, the top post was never contested in the BJP, unlike the Congress which held polls twice to elect its president. It was either the RSS’s writ that prevailed, pre-empting the inevitability of a contest that would have undermined the Sangh’s own authority or the parivar’s unified purpose to reach the commanding heights which disallowed disruptions in an all-important quest for absolute power.The current incumbent, J P Nadda, leads a charmed life. The soft-spoken and amenable party president—who has no choice but to lie low in the highly centralised power structure run by the Modi-Shah duopoly—is nearly at the end of a five-year term. It’s a record in a party whose Constitution stipulates two terms of three years each to a president. He stepped into the post once Amit Shah demitted office in 2019 on becoming a central minister.Nadda hangs on to the post even after his induction in the Union cabinet, which was believed to be the first sign that a successor was being reined. His continuance has virtually put to rest the ‘one person, one post’ principle. But who cares for the party’s Constitution any longer? When an old-timer timorously brought up the subject of not adhering to the book at an internal meet, he was told that the Constitution existed because of the party and not the other way—so there was no need to obsess over its importance.

Where is the much-awaited successor? A plethora of names are bandied about periodically. But like the cat with nine lives, each time the succession chatter gains momentum, Nadda manages to survive. He was seldom embroiled in a controversy like his role model, former party president Kushabhau Thakre, who served during Atal Bihari Vajpayee’s prime ministerial tenure.

Public faith in judiciary at stake

The higher judiciary serves as a bulwark against injustice. If the judiciary hesitates to step in to restore people’s faith in a just order, we as a nation stand doomed.

A three-member committee comprising two Chief Justices of high courts and a judge of a third high court, selected by then Chief Justice of India (CJI) Justice Sanjiv Khanna, examined more than 60 witnesses and inspected the residential premises. The panel concluded that Justice Varma could not explain satisfactorily the presence of sacks ofRs 500 notes, some of them damaged by the fire. The committee recommended impeachment proceedings against the judge as this was the course prescribed in the Constitution for the dismissal of a Supreme Court (SC) or high court judge.The CJI and the SC’s Collegium of senior judges recommended Justice Varma’s transfer back to the Allahabad High Court, his parent HC, in March itself. The CJI had instructed the Chief Justice of the Delhi High Court not to allot judicial work to Justice Varma while he was in the Capital.The CJI at that time had an onerous duty to perform. He was well aware that public trust in the integrity of the higher judiciary had to be salvaged. At the same time, no scope should be left for people to think that the judiciary at the highest level was involved in any form of cover-up of a recalcitrant brother judge. In my opinion, the CJI passed the test with distinction. He opted for transparency, a route rarely favoured by government agencies under attack.

The judiciary and the armed forces of the country are the only two institutions left which people still respect. All others, including the media to a great extent, have fallen by the wayside. If these holdouts are politicised or weakened by corruption, the present system of governance would slip into full-fledged dictatorship.

The higher judiciary serves as a bulwark against injustice. When winning elections at any cost becomes more important than ensuring good governance by upholding the rule of law, instances of injustice are bound to increase. If the judiciary hesitates to step in to restore people’s faith in a just order, we as a nation stand doomed!Corruption in the judiciary is becoming a problem. The CJI and other senior judges should sit up and take notice. As corruption in society increases, as it is happening today, leaders from all walks of life should ponder over measures to combat the disease. Prime Minister Narendra Modi used to say that he would not touch tainted money and also not allow those under his watch to do so.It is to be noted that he has not been repeating this boast nowadays. Corruption in public life goes on as merrily as before. Even his party, which was voted to power in 2014 as it swore to end corruption, has not bucked the trend. Having completed 11 years in power, Modi’s party is absorbing in its ranks assorted Congressmen, Shiv Sainiks and others who had been named and even prosecuted by his government for big-time corruption. An English term, “washing machine”,



has entered common parlance in Mumbai. Former Cabinet Secretary BG Deshmukh was a good friend of mine. He and I, along with Dr Raj Kumar Anand, a leading paediatrician of Mumbai, formed the Public Concern for Governance Trust (PCGT). The Trust concentrates on college and school students, trying to make them good citizens by imbibing good values. We felt that this was the only way concerned citizens like us could contribute to fight corruption.A girl who served on the staff of our NGO competed for a First-Class Judicial Magistrate’s appointment in Maharashtra. She was selected. Having worked with our NGO, where she herself was involved in spreading noble values among the youth, we are confident that there will be at least this one dispenser of justice to perform her dharma, as the Gita expects every good human to do without any expectation of a reward. The PCGT’s trustees will follow her career with much interest.Reverting to Justice Varma’s case, some previous impeachment proceedings went in vain. This may not happen this time round as the BJP has taken the correct stand, supporting the findings of the three-member committee which passed muster with the

collegium of five senior judges of the Supreme Court. Opposition parties cannot afford to vote against this motion.

In a court of law, it might have been more difficult, though not impossible, to sustain the charges. The main omission of counting the burnt and unburnt notes could come to the rescue of the accused. The leading legal luminary who has taken the judge’s brief will certainly play up this defect in the prosecution case.The firemen and the security detail who were the first responders talked of sacks of currency notes and burnt notes scattered on the ground. If a HC judge was not involved, the panchnama would have been drawn up. It would have sealed the culprit’s fate. But the imperative of informing the CJI and getting his consent at each stage threw up impediments to the normal procedure. Three judges of repute have concluded that sacks of money were seen by the first responders but were removed by Justice Varma’s personal staff before the Delhi High Court officials could arrive at the scene. The then CJI’s decision to hide nothing from the public and keep it informed at all stages has helped to build public trust in the higher judiciary, but there is a long road ahead.

Develop a robust aviation maintenance ecosystem in India

The safety of the millions flying every day rests squarely on ensuring the regulator tasked with overseeing it has the resources to perform its job. The recent crash unequivocally underscores this

The recent Air India crash, whose causes are still being investigated, casts a harsh light on an issue critical for aviation safety—the country’s maintenance, repair and overhaul (MRO) ecosystem. It’s not merely about fixing aircraft, but having a well-regulated backbone to ensure that every plane taking off is fit to do so. MRO is not an option; it’s a critical pillar of aviation safety. However, the sector is in a nascent stage in India even after years of regulatory efforts to establish an ecosystem. The crash and the frequent flight cancellations due to technical glitches should be seen as a warning for the government to address the challenges the sector faces and clear the hurdles to its development.The Directorate General of Civil Aviation (DGCA)—the body that oversees aviation safety and enforces MRO standards in the country—faces its own share of challenges. A Parliamentary Standing Committee report tabled just days before the Air India incident highlighted that the DGCA is facing a staggering 53 percent vacancy. How can the country’s primary safety regulator effectively



audit MRO providers, ensure compliance with complex civil aviation requirements and oversee a rapidly expanding sector—reflected in the number of airports growing from 74 to 220—with over half its sanctioned posts vacant? Similarly high levels of vacancy plague the Bureau of Civil Aviation Security, which is responsible

for security, and the Aircraft Accident Investigation Bureau. All this adds up to a systemic oversight deficit in the country. The domestic MRO sector is hobbled by some inherent deficiencies. A Niti Aayog report has highlighted manufacturing monopolies that restrict access to vital data and manuals, inadequate infrastructure such as modern hangars and specialised training facilities, and a lack of universal recognition for DGCA’s certifications, which severely hinders India’s ability to undertake high-value MRO work. While policy adjustments like GST reduction are welcome steps, they alone cannot address the foundational issues hampering the sector’s growth and efficacy. The safety of the millions

flying every day rests squarely on ensuring the regulator tasked with overseeing it has the resources to perform its job. The recent crash unequivocally underscores this. Building a robust MRO infrastructure and filling critical regulatory vacancies are not avoidable expenses—they are essential investments needed to save lives.

Family values: Court affirms Tamil Nadu’s inclusive gender traditions

Madras High Court’s ruling that same-sex couples can form a family is a testament to Tamil Nadu’s progressive legacy rooted in Indic traditions, activism and legal reforms. The state has led in establishing significant milestones for LGBTQIA+ rights in the country

In a landmark ruling delivered earlier this month, the Madras High Court affirmed that same-sex couples can form families without legal marriage. It marked a major milestone for LGBTQIA+ rights in India, particularly in Tamil Nadu. Emerging from a habeas corpus petition, the ruling addressed the case of a 25-year-old lesbian woman detained by her natal family. Her partner sought her release so that they could live together. While securing her freedom, Justices G R Swaminathan and V Lakshminarayanan expanded the definition of family under Indian law, emphasising personal autonomy and right to self-determination.

It comes decades after the 2002 suicide of two lesbian women in Erode’s Satyamangalam forest after facing societal rejection of their relationship. Despite this, the 2025 verdict builds on Tamil Nadu’s progressive legacy rooted in both legal reforms and Indic traditions fostering wider acceptance of diverse identities. The verdict signals progress while recognising the concept of a “chosen family” under Article 21 of the Constitution, which guarantees life and personal liberty. The court’s assertion that “marriage is not the sole mode to found a family” validates non-traditional relationships and offers hope where despair once prevailed.Despite a section of society refusing to accept gender-diverse communities, every May to July, vast numbers of indigenous gender-variant and diverse SOGIESC (sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristics) communities in south India honour their patron deities at temples such as those for Koothandavar Aravan in Tamil Nadu, and for Ellamma, Bhagavati and Mariamman across the

region. These communities enact gender-specific Hindu rituals, which have historically provided sacred spaces for early LGBTQIA+ activism. This cultural acceptance, though not universal, has helped shape a more inclusive societal framework and complemented the legal efforts.

The court’s legal reasoning in the latest case was meticulous. The detainee confirmed her lesbian identity and desire to live with her partner, exposing familial coercion. The judges, referencing the Supreme Court’s 2023 ruling in the Supriyo @ Supriya Chakraborty case, noted while same-sex marriage remains unrecognised, same-sex couples can still form families. The court criticised police inaction and directed law enforcement to protect the couple, reinforcing the judiciary’s role in safeguarding individual rights against societal and familial pressures

Tamil Nadu’s history of activism and legal milestones has been crucial in reaching this point. In 1994, former Chief Election Commissioner T N Seshan granted voting rights to transgender individuals, setting a precedent for inclusion. In 2004, advocate G R Swaminathan, now a judge, secured voter identity cards for transgender people, prompting the state to publicise their voting rights. By 2006, a government order aimed to improve transgender living conditions, promoting counseling to prevent disownment and ensure educational access.

In 2008, Tamil Nadu established a transgender welfare board, and in the early 2000s, it introduced one of India’s first transgender welfare policies, offering free gender-affirming surgeries and socio-economic benefits. Asia’s first Genderqueer Pride

Parade and Education Fest for school children and college students were organised in 2012. Anjali Gopalan of Naz Foundation flagged off the event in Madurai. In 2019, the Madurai bench of the Madras High Court led by Justice Swaminathan banned forced sex-selective surgeries on intersex infants, making Tamil Nadu the first state to do so. It also



became the first to recognise and register marriages of transgender and intersex persons under the Hindu Marriage Law, amend police guidelines to prevent harassment of the LGBTQIA+ community, ban conversion therapy, and include LGBTQIA+ issues in curriculums in 2017.

Organisations like Srishti Madurai and Orinam Collective have supported these efforts through legal petitions, providing shelters, funds and organising workshops, pride parades, embedding queer rights within Tamil Nadu’s cultural and legal fabric. Today, the Tamil has native terminologies for diverse SOGIESC identities, which is missing in many Indian languages. Festivals and rituals at temples like Koothandavar

Aravan, where gender-diverse individuals are celebrated, has provided a foundation for LGBTQIA activism. These sacred spaces, where GIESC communities perform rituals honoring deities associated with fluid gender identities, have historically challenged societal norms, fostering a sense of belonging and resistance against discrimination. This cultural acceptance, though not without resistance, has been a catalyst for legal victories, like the latest ruling, which resonates with the communal spirit of these traditions.

Despite these advancements, challenges persist. The 2002 suicide underscores the personal struggles behind legal battles. Activists say societal acceptance often lags behind legal progress, with financial hardships and exclusion remaining prevalent.The latest verdict complements rulings by former Chief Justice D Y Chandrachud and Justice Venkatesh of Madras High Court, creating an ecosystem where personal identity and relational freedom are upheld as matters of dignity and public interest, the ruling has sparked broader discourse on queer rights, inviting debate on legal recognition of diverse family structures. It signals a future where all, regardless of sexual orientation, can live with integrity and autonomy.

The ruling is a testament to the enduring power of activism Activists are continuing to push for comprehensive legal recognition, including same-sex marriage, and cultural acceptance to address ongoing discrimination. Building on decades of progress, the latest judgement ensures that love in all its forms is protected, offering a path towards an inclusive future where past tragedies are not repeated.

Sensex ends 300 points higher, Nifty above 25,600; Jio Financial shares jump 4%

New Delhi. Benchmark indices closed higher for the fourth straight session on Thursday, buoyed by easing global concerns and renewed foreign inflows. The S&P BSE Sensex rose 303.03 points to end at 84,058.90, while the NSE Nifty50 gained 88.80 points, settling at 25,637.80. All broader market indices also finished in positive territory as volatility eased, bringing both key benchmarks within striking distance of new record highs.Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services, said recent global developments have lifted market sentiment.“Key catalysts like the ceasefire in the Middle East and optimism around easing trade tensions have cleared investor concerns. After several sessions of selling, FIIs have turned net buyers, which is helping stabilise the market,” he said. “Benign oil prices, a stronger rupee, and steady macroeconomic indicators are driving interest in domestic growth themes. Expectations of stronger earnings, supported by resilient consumption, are further boosting optimism.”

Pump and dump scam: Sebi says has raided many shell companies

MUMBAI. Markets watchdog Sebi has confirmed reports in a section of the media that it had carried out raids in multiple locations and on multiple shell companies for what it considers to be cases of pump and dump scams.“Sebi has conducted search and seizure operations at multiple locations in June in connection with pump and dump in certain scrips and has seized incriminating evidence,” Sebi said in a statement Friday, confirming various news reports regarding its raids in the pump and dump scam.“Further investigation in the matter is under progress,” the regulator added in the statement without offering any more details such as the number of companies raised or the value of the alleged scam etc.Some section of the media has been reporting since last week that Sebi raided around two dozen shell companies involved in the Rs 300-crore pump and dump scheme across Ahmedabad, Mumbai and Gurugram. These raids are one of the biggest in Sebi’s history in terms of monetary value. The raids primarily involved 15-20 shell companies which were allegedly created by promoters of some listed companies to pump and dump their own shares. At least two listed agro-tech companies along with their promoters are said to be at the helm of the alleged network, sources had said.“Sebi has seized several documents including company documents, rubber stamps. Preliminary assessment suggests the scam was at least Rs 300 crore, however more details would emerge once the seized documents are analysed,” a source was quoted by one such report. Generally, in cases of pump and dump schemes, Sebi issues an order against the entities. In in very few cases, Sebi also uses its search and seizure powers against the entities like in the current case.The pump and dump scam works in the following manner: promoters create shell companies and register them as proprietary traders which will buy and sell the company stocks later. In the past, there have many instances where Sebi has gone after promoters of small and mid-cap companies for manipulating their stocks.In a pump and dump scheme, entities related to the scamsters first start buying shares of own companies in large numbers to drive up the stock price and once the price has gone up significantly, it catches the attention of retail investors and the manipulators then exit the stock at a profit by selling the shares to gullible retail investors.

Output of farm sector rises to Rs 29.49 lakh crore in FY24: Govt data

New Delhi. The Gross Value of Output (GVO) from the agriculture and allied sector increased 54.6 percent from FY12 to FY24 to Rs 29.49 lakh crore at constant prices, the National Statistics Office (NSO) said on Friday.The NSO, part of the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), has released the annual publication of ‘Statistical Report on Value of Output from Agriculture and Allied Sectors (2011-12 to 2023-24)’.“Gross Value of Output (GVO) from the agriculture and allied sector at constant prices has shown steady growth from Rs 1,908 thousand crore in 2011-12 to Rs 2,949 thousand crore in 2023-24, marking an overall increase of approximately 54.6 percent,” NSO said.It further said the Gross Value Added (GVA) of agriculture and allied sectors at current prices registered a growth of about 225 percent, increasing from Rs 1,502 thousand crore in 2011-12 to Rs 4,878 thousand crore in 2023-24. The publication is a comprehensive document that provides detailed tables on values of output of crop, livestock, forestry and logging, and fishing and aquaculture sectors of agriculture and allied activities from 2011-12 to 2023-24 at both current and constant (2011-12) prices.The detailed publication comes after the major aggregates at the all-India level have been released in the form of National Accounts Statistics on 28th February 2025, NSO said.According to the data, the crop sector with GVO at Rs 15.95 lakh crore remains the largest contributor to total GVO (at constant prices) of agriculture and allied sectors with a share of 54.1 percent in 2023-24. Cereals and fruits and vegetables together accounted for 52.5 percent of total crop GVO in 2023-24.Among the cereals, only paddy and wheat constituted approximately 85 percent of GVO (at constant prices) of all cereals in 2023-24.Five states—Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Telangana, and Haryana—contributed nearly 53 percent of GVO (at constant prices) of cereals in 2023-24.With a reduced share (18.6 percent in 2011-12 to 17.2 percent in 2023-24), Uttar Pradesh maintained the top position, according to the NSO data.In the fruit group in 2023-24, the constant price GVO of bananas (Rs 47,000 crore) has surpassed that of mangoes (Rs 46,100 crore). Mango was the top-most contributor in GVO (at constant prices) in the fruit group consistently from 2011-12 to 2021-22.

IndusInd Bank shortlists 3 names for top job ahead of RBI deadline

The bank is run by an RBI-approved executive committee comprising its consumer banking head Soumitra Sen and the chief administrative officer Anil Rao.

MUMBAI. The troubled IndusInd Bank, which has been headless since late April when the scam-tainted chief executive Sumant Kathpalia and his deputy Arun Khurana resigned owning moral responsibility for the massive losses in its forex derivatives trading book, has reportedly shortlisted three names--Rajiv Anand of Axis Bank, Anup Saha of Bajaj Finance, and Rahul Shukla of HDFC

Bank--to man the top deck.While Rajiv Anand is currently the deputy managing director of Axis Bank, Anup Saha is the managing director of Bajaj Finance, and Rahul Shukla is the group head of commercial and rural banking at HDFC Bank and is on a sabbatical from the largest private sector bank. While Sumant Kathpalia resigned on April 29, his deputy Arun Khurana did so a day before. Both had cited moral responsibility for the scam for the decisions to leave, which came in well after seven weeks since the crisis came out. Both have also been banned by the market regulator from the market for insider trading—they had pocketed over Rs 157 crore from selling bank’s shares in 2023-24.Since their resignations, the bank is run by an RBI-approved executive committee comprising its consumer banking head Soumitra Sen and the chief administrative officer Anil Rao. According to a source in the know of the development, the board of the Hinduja group-promoted bank is expected to clear

these names and submit the list to the Reserve Bank for approval any day now before the regulatory deadline of June 30. The regulator has also asked the board to suggest probable names only from



outside IndusInd Bank. During a recent analyst call, IndusInd chairman Sunil Mehta had assured stakeholders that the names would be submitted well before the deadline.The upcoming leadership change is seen as a crucial development for the bank, which has been in focus since early March when it was forced by the RBI to inform all stakeholders that it

made accounting mistakes in the forex derivatives books for several years and that it would have to make provisions to the tune of 1.35% of its net worth as of December 2024 when it was Rs 64,000 crore.But the bank on May 22 said while announcing the March quarter earnings that the losses were much higher at Rs 2,329 crore. It had booked a net profit of Rs 2,349 crore in the year-ago period. Most of the loss was due to the impairment in its forex derivatives book, which the management first said would be only around Rs 1,600 crore.The lender reported net interest income of just Rs 3,048 crore in Q4 a whopping 43% less from Rs 5,376 crore a year ago.The 59-year-old Rajiv Anand of Axis Bank has over 35 years of experience in the financial services sector. He began his journey at Axis Asset Management Company in 2009 as its founding managing director and chief executive. In 2013, he moved to Axis Bank as president of retail banking, eventually joining the board in the same year.

HDFC Bank slashes FD and savings rates again in June. Details here

HDFC Bank's latest changes signal that deposit rates could remain soft if the RBI continues its rate-cutting cycle. Depositors should review their plans, stay updated with rate changes, and make informed decisions before booking new FDs or Rds.

New Delhi HDFC Bank has again cut its fixed deposit (FD) interest rates this month. This is the second rate cut in June 2025 for India's largest private bank. From June 25, 2025, the bank has lowered the interest rate on single FD tenures by 25 basis points (bps) for deposits below Rs 3 crore.This follows a similar cut made earlier on June 10, 2025, after the Reserve Bank of India (RBI) reduced the repo rate by 50 bps, from 6% to 5.5%. WHICH FD TENURE IS AFFECTED? HDFC Bank has reduced the interest rate on FDs with a tenure of 15 months to less than 18 months. Earlier, this rate was 6.60% for general customers and 7.10% for senior citizens. Now, it is 6.35% for general customers and 6.85% for seniors.The bank offers FD rates from 2.75% to 6.60% for the general public (for 18 months to less than 21 months) and 3.25% to 7.10%



for senior citizens for amounts under Rs 3 crore. PENALTY FOR PREMATURE WITHDRAWAL If you need to break your FD early, remember that the bank charges a penalty. According to HDFC Bank's rules, if you withdraw your FD before maturity, you will get 1% less than the rate applicable for the period your money stayed with the bank, and not the original contracted rate. SAVINGS ACCOUNT RATES ALSO REDUCED

Along with the FD rate cut, HDFC Bank has also lowered the interest rate on all savings accounts. From June 24, 2025, the savings rate is down by 25 bps, i.e., from 2.75% to 2.50% per annum for all balances.The savings account interest is calculated daily and paid every three months. WHAT ABOUT RECURRING DEPOSITS? The bank's recurring deposit (RD) interest rates remain between 4.25% and 6.60% for general customers and 4.75% to 7.10% for senior citizens, depending on the deposit period. These rates have been in effect since June 10, 2025. WHAT IT MEANS FOR CUSTOMERS With two rate cuts in a single month, HDFC Bank customers will now see slightly lower returns on fresh FDs and savings accounts.

Weekly Review: Gold prices fall as investors turn away from safe-haven assets

CHENNAI. Gold prices have recently declined, marking their second consecutive weekly loss, as investors increasingly shift focus away from traditional safe-haven assets. The weakening demand for gold comes amid a broader surge in risk appetite, buoyed by rising equity markets, easing geopolitical tensions, and firming expectations of a stable macroeconomic environment. In India, the precious metal prices have eased this week, offering a potential buying opportunity. On June 28, the price for 22-carat gold fell by about Rs55 per gram from the previous day—now around Rs. 8,930 per gram—while 24-carat gold was Rs. 9,742 per gram. Over the last ten days, 22-carat prices have dropped from Rs. 9,265 on June 19 to Rs. 8,930 on June

28—a fall of roughly Rs. 335. Similarly, 24-carat gold fell from Rs. 10,108 to Rs. 9,742—a Rs. 366 decline.



This downward trend reflects a broader global correction, driven by easing geopolitical tensions (such as the Israel-Iran ceasefire), a stronger dollar, and rising U.S. Treasury yields reducing the appeal of non-yielding

assets like gold . In MCX futures, domestic prices dropped about Rs. 1,630 per 10g this week amid reduced safe-haven demand. For buyers, this dip may be a good chance to purchase jewelry or invest—but it's wise to monitor global trends, interest rates, and inflation data for future movements. Spot gold dropped by approximately 1.2% to around \$3,288 per ounce, while US August futures fell by 1.7%, closing the week with a nearly 3% decline. This drop reflects investor preference for higher-yielding or growth-oriented assets, with the Nasdaq hitting fresh record highs—signaling a strong risk-on sentiment in the market. Gold's earlier rally, which saw prices touching historic highs earlier this year, has also prompted technical profit-taking, accelerating the recent sell-off.



marriage.WHY IS THE CHANGE NEEDED The EPFO, which serves over 7 crore people, first brought in online auto-settlement for advance claims during COVID-19 to help members in financial need. Yet, people still need to file claims to get their EPF. The new plan hopes to cut out this step and lighten the EPFO's load, as it deals with over 5 crore withdrawal requests annually.The official added that this new plan aims to cut down on paperwork and save time for both the EPFO and its members. However, the EPFO cannot directly allow cash withdrawals like a bank because it does not have a banking licence. So, the government is trying to upgrade EPFO's services so they work more like regular bank services.

Wall Street rallies to record highs as AI stocks soar, recession fears ease

US stock markets hit all-time highs on Friday thanks to an AI boom and Fed hints at looser policy ahead. Trade deals with the UK and China have also fuelled market hopes that a global recession could be avoided.

New Delhi. The S&P 500 and Nasdaq Composite hit all-time highs on Friday as megacap stocks surged on renewed AI enthusiasm and the prospect of a looser monetary policy, powering a recovery in US stocks from months-long rout.The benchmark index rose 0.2% to 6,154.81 points, surpassing the previous peak of 6,147.43 on February 19, while the tech-heavy Nasdaq gained 0.3% to 20,229.31 points, exceeding its record high of 20,204.58 on December 16.Markets



rallied this week as an upbeat forecast from chipmaker Micron brought back investor confidence around artificial intelligence, while AI bellwether Nvidia hit a record high to reclaim its position as the world's most valuable company.Risk appetite also benefited from a US-brokered ceasefire to a 12-day air battle between Israel and Iran that sparked a

jump in crude prices and raised worries of higher inflation.Dovish remarks from Federal Reserve policymakers have also aided sentiment.Trump's April 2 "reciprocal tariffs" on major trading partners and their chaotic rollout had put the S&P 500 within a striking distance of confirming a bear market when it ended down 19% from its February 19 record

closing high.The Nasdaq had tumbled 26.7% from its previous peak, marking a bear market days after Trump's "Liberation Day" on April 2.Since then, US trade deals with the UK and China have firmed up market expectations for more such agreements on the hopes that a global recession could be avoided.The S&P 500 has surged more than 23.5% and the Nasdaq about 32% since their recent lowest close on April 8, largely powered by a handful of megacap stocks such as Microsoft, Nvidia, Meta Platforms and Amazon.If the Nasdaq closes above the December 16 record close at 20,173.89, it would be the end of the bear market and start of a new bull market, according to common definitions.A bear market is defined as a 20% decline from a record high close, on a closing basis.Both the Nasdaq and S&P 500 have gained 4.4% this year as of Thursday's close. The blue-chip Dow has risen about 2% this year and remains about 3.7% below its all-time peak.

In first meeting of MCD's Standing Committee, 25 proposals get nod

The delay caused due to a tussle between AAP and BJP had ended with the appointment of BJP councillor Satya Sharma as chairperson on June 12

Agency New Delhi.

Poor sanitation, dog menace, monsoon preparedness, and status of desilting were among the few issues discussed on Friday at the first meeting of the Municipal Corporation of Delhi's (MCD) Standing Committee, a body set up after a delay of two-and-a-half years.

The delay caused due to a tussle between AAP and BJP had ended with the appointment of BJP councillor Satya Sharma as chairperson on June 12. Every project worth over Rs 5 crore needs to be passed by this committee.

At the meeting on Friday, Sharma announced that the deadline for availing a 10% rebate on property tax has been extended till July 31.

Over 25 items on the agenda were passed at the meeting, including the purchase of Diflubenzuron

25% WP, used to kill mosquito larvae in its initial stage. This is in line with the initiative taken up by MCD's Public Health department to prevent and control of vector-borne diseases ahead of the monsoon.

Also passed were items related to the revision of the layout plan of DDU Marg, as well as Delhi University colleges, including Shri Ram College of Commerce (SRCC) and St Stephen's College.

The proposal for SRCC included the construction of a new academic block and the addition of two floors for a girls' hostel. The approval for this proposal had been pending since 2012. For St Stephen's College, the approved proposal included the addition of a new academic block, a hostel



block, staff quarters, and an auditorium block. A proposal in this regard had been pending for the last 10 years.

The meeting also approved the extension of contract for private security services, sanitation workers, and housekeeping staff at MCD-run hospitals such as Kasturba Hospital, Rajan Babu Institute of Pulmonary Medicine and Tuberculosis and Maharishi Valmiki Infectious Diseases

Hospital.

Leader of Opposition, AAP councillor Ankush Narang, meanwhile, raised the issue of poor sanitation in Central, West, and South zones, questioning the budget sanctioned to each councillor.

At the meeting, councillors sought status and data on drains desilted ahead of monsoon, open drains, JJ Colony clusters, encroachments, illegal parking, and vacant posts of sanitation workers, among others.

A civic body official said, "Authorities have hastened the process of desilting. Till now, 1.56 lakh metric tonne of silt has been removed, while 37,000 small drains have been desilted against the 40,000 target."

Delhi bans fuel for old vehicles from July 1: How will defaulters be tracked?



Agency New Delhi.

Starting July 1, Delhi will stop supplying fuel to all overage vehicles. As part of this effort, the Transport Department, the Traffic Police, and the Municipal Corporation of Delhi (MCD) will work together to identify hotspots that see a high number of such vehicles attempting to pass through the city. These vehicles will be identified by ANPR (Automatic Number Plate Recognition) cameras that have been installed at 498 fuel stations, officials said Friday.

According to directions issued earlier this year by the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM), all end-of-life vehicles (ELVs) — 10 years for diesel vehicles and 15 years for petrol ones — will be denied fuel starting Tuesday. From October 31, the plan comes into effect in five high-vehicle-density districts of Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, and Sonapat.

Niharika Rai, Secretary-Cum-Commissioner, Transport Department, said the number of ELVs arriving at a fuel station will be noted, as it could be a proxy for vehicle owners residing in nearby areas. Targeted action will be taken at such fuel stations, Rai said. "Joint teams of the transport department, traffic police and MCD will be deployed at all identified fuel stations reporting a high number of such vehicles."

Ajay Chaudhary, Special Commissioner (Traffic), Delhi Police, said, "The departments are still assessing how the teams should be deployed as a few fuel stations work around the clock, but others work for a few hours." He emphasised that there will be no loopholes and the plan will be implemented stringently, as all staff at fuel stations have also been trained.

Delhi: Man on scooter dies after throat slit by Chinese manjha

Agency New Delhi.

A 22-year-old man died after his throat was slit by a banned Chinese manjha — a sharp string used for flying kites — while he was riding his scooter near Bara Hindu Rao Hospital in North Delhi on Friday evening. Chinese manjha, which is coated with glass, metal, or other sharp materials, has been banned in the Capital since 2017.

Police said the victim, Yash Goswami, a resident of Karawal Nagar, was on his way home when he came in contact with the sharp thread near the Rani Jhansi flyover. "Goswami suffered a deep cut on his neck, causing him to collapse on the spot. He was rushed to the hospital by passersby, where he was declared dead on arrival," a police officer said.

Goswami used to run an auto parts shop in Karol Bagh. He was alone at the time of the incident but was wearing a helmet, the officer added.

Police said a case under Section 106(1) (causing death by negligence) of the BNS has been registered against unknown persons at Bara Hindu Rao police station. "The crime scene was inspected by the forensics team, and strands of Chinese manjha were recovered from the body as well as from the scooter," another officer said.

This is not the first incident of Chinese manja claiming lives in the Capital. In July 2023, in West Delhi's Paschim Vihar, a seven-year-old girl lost her life after the thread slit her neck while she travelling with her parents on a scooter.

Last year, in August, a 47-year-old Assistant Sub-Inspector (ASI) of the Delhi Traffic Police and a 34-year-old businessman were injured by the abrasive string in two separate but similar incidents in Northeast Delhi. Cracking down on the illegal stocking of Chinese manja, the Delhi Police Crime Branch had conducted a raid in Rohini in August 2024. During the raid, they recovered around 12,000 reels of illegal Chinese manja and arrested three people for stocking it.

Faridabad murder: Police await post-mortem report to confirm rape by victim's father-in-law

Agency Faridabad.

The Faridabad police, probing the murder of a 25-year-old woman, whose decomposed body was found buried in a pit, is awaiting the post-mortem report to confirm the rape confession of the victim's father-in-law, who allegedly strangled her in April.

The Crime Branch-DLF, Haryana Police, have added rape charges against the father-in-law, who was arrested on June 20, the same day the woman's body was recovered outside his house in Faridabad.

A police officer told while the accused had stated during interrogation that he had allegedly raped the deceased, before the murder, they are awaiting the medical and post-mortem reports of the deceased are still awaited. "He did not tell the family about the (alleged) rape," the officer said.

Five days after the decomposed body was found beneath a concrete slab, the Crime Branch on June 25 arrested her mother-in-law in the case. The case was initially being probed as a dowry dispute.

The father-in-law had allegedly confessed that the family had conspired to murder the daughter-in-law due to ongoing domestic disputes, including talks of divorce.

According to the police, the father-in-law had allegedly revealed that he and his family had plotted the murder a week before the incident. On April 21, he allegedly sent his wife to her relatives in Uttar Pradesh. The same day, a pit was dug outside their house, the police had said.

The victim was allegedly given sugarcane juice laced with sleeping pills by the father-in-law, and later that night, while she was unconscious, he strangled her with a dupatta. Her body was then buried in the pit with her husband's assistance, the police said, adding that the family subsequently reported that she had gone missing to mislead people. The police had initially registered a missing case based on a complaint by the husband on April 25. While the husband is absconding, the role of the husband's sister is under investigation. However, the police intensified the investigation following suspicions and complaints from the deceased's father that her in-laws were involved in her disappearance.

Minor boy, tailor stabbed to death in separate incidents in Delhi's Rohini

Agency New Delhi.

Two people, including a 15-year-old boy, were stabbed to death in separate incidents which took place within a span of two hours in Rohini's Aman Vihar area on Thursday evening, the Delhi Police said.

According to the police, at 8.30 pm on Thursday, they received a call about two siblings being stabbed by a group of people in the Aman Vihar area, with one of them succumbing to the injuries. The deceased was identified as Praveen, 25, a tailor who had been living in Aman Vihar's Balveer Nagar for the past two months.

A police team rushed his brother Deepak to Sanjay Gandhi Hospital where he was reportedly in a critical condition.

A police officer said Praveen and Deepak were on their way to buy vegetables on Thursday night when some assailants attacked Praveen with knives. Deepak intervened to save his brother, but was also stabbed by the attackers, who then fled.

"Praveen had an altercation with some local residents earlier this month, and they were allegedly looking for revenge. The assailants have been identified and attempts are being made to nab them," an officer said.

Just two hours before the incident, at 6.30 pm, Aman Vihar police received another call about a 15-year-old boy being stabbed to death by boys in his neighbourhood.

According to a senior police officer, the boys who attacked the Class 10 student had an argument with him and his friends at a park in Rohini's Sector 20. "Three to four boys came to the park where the deceased was with his friends. The deceased got into an argument with the visiting boys, who then started beating him," a police officer said. Four friends of the deceased then stepped in to help him, upon which the attackers took out knives and stabbed all five.

The police rushed all five injured to Sanjay Gandhi Hospital, where the 15-year-old boy was declared dead. His friends are currently under treatment, the police added. No arrest was reported in connection with the stabbings till Friday night.

Delhi BJP chief accuses ILBS of labour & PF law violations

In his letter, Sachdeva wrote, "The specific issue relates to PF contributions being made by the institute, which, as per information received, are not in compliance with statutory requirements"

Agency New Delhi.

Delhi BJP president Virendra Sachdeva has written to Central Provident Fund Commissioner Ramesh Krishnamurti alleging serious violations of labour laws and provident fund regulations at the Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS), an autonomous institution under the Delhi government.

In a letter dated May 15, Sachdeva alleged that the employer's contribution towards provident fund (PF) at the super-speciality hospital for liver and biliary diseases is reportedly limited to only 8% of the employees' salaries, in contravention of the statutory requirement of 12%. He alleged that an equivalent amount is deducted from employees' salaries.

When asked, ILBS Director Dr S K Sarin said, "So far, I have not received any complaint from anyone." Sarin further

said that he will look into the details as soon as he receives any official intimation.

In his letter, Sachdeva wrote, "The specific issue relates to PF

Organisation (EPFO) are shown to be lower than the actual amounts, thereby misrepresenting the contribution as compliant," he added. This manipulation not only violates the

Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, but also undermines the financial security of the employees, he further said.

"Moreover, it is alleged that these actions are taking place with the full knowledge and complicity of senior officials at the institute. Employees, most of whom are on contractual appointments, reportedly refrain from raising these issues formally due to fear of termination and other reprisals. I am also informed that these irregularities have been going on for a few years now and largely unchecked," he said in his complaint. Despite attempts, Sachdeva could not be contacted for a response.



This park in Delhi could soon be 'pollution-free'. Here are the details

The previous AAP Delhi government had explored various measures to control air pollution, including the installation of two smog towers at Connaught Place and Anand Vihar

Agency New Delhi.

The Delhi government has an ambitious plan up its sleeve to turn the famed Nehru Park in the diplomatic enclave of Lutyens' Delhi into a 'pollution-free zone' — by installing 'modern air purifiers' equipped with a unique system to capture and store polluting particles, said officials.

According to Environment Minister Manjinder Singh Sirsa, the New Delhi Municipal Council (NDMC) first installed the air purifiers on a trial basis at four locations — Anand Vihar ISBT in 2023, Ambassador hotel in Khan Market, and New Moti Bagh in 2024, and Jangpura in January 2025 — which were successful. "The government is planning to extend this

initiative on a large-scale basis, starting with Nehru Park... The premises has a good green cover. But



when the air-quality level deteriorates overall, it also affects this space — even if the AQI is better than other locations. So, with these machines, we want to make this park pollution-free," he said. Officials said the locations for

the trial run were selected based on whether they saw a large influx of vehicles or where pedestrian footfall was high.

"For instance, Anand Vihar-ISBT sees buses passing through, it has a high footfall, and there is construction work going on. So, this spot was suggested by the Commission for Air Quality Management. In Jangpura, the machines were installed at a petrol pump, which also sees vehicles passing through. As for the two other locations, one is a residential area and the other a hotel. Thus, the key aim is to reduce harmful exposure to people in outdoor spaces that see a high footfall," said an official.

Delhi govt schools directed to set up Special Admission Cells for children out of school

The cells have been tasked with ensuring smooth and time-bound admission of identified out-of-school children, including those with special needs, in Delhi.

Agency New Delhi.

Delhi's Samagra Shiksha Department has directed the heads of all government schools, including that of the Directorate of Education (DoE), Municipal Corporation of Delhi (MCD), New Delhi Municipal Council (NDMC) and the Delhi Cantonment Board (DCB), to set up Special Admission Cells (SAC) for children who were never enrolled.

According to a circular issued on Thursday, the department aims to "strengthen and streamline the admission process of never-enrolled Out-of-School children (OOSC), including Children with Special Needs (CWSN)" as well as students who dropped out of the school system due to any reason.

These cells need to comprise the school head, admission in-charge and an educational and vocational guidance counsellor (EVGC) or a representative of similar expertise from the management belonging to MCD, DCB or NDMC authorities. There also has to be a Cluster

Resource Centre Coordinator (CRCC) to give data to the cell.

The SAC has been tasked with ensuring smooth and time-bound admission of identified out-of-school children, including Children with Special Needs. It is also expected to guide and counsel parents and children during the admission process. According to the circular, the SAC should ensure minimal documentation and coordinate with the school head and Special Training Centre (STC) teachers for enrolment support. Other responsibilities listed include:

To monitor retention, attendance

Follow up on absenteeism and academic progress of the admitted out-of-school children. These need to be done by maintaining their records.

Review the progress of out-of-school children by holding periodic meetings



Coordinate with the Cluster Resource Centre Coordinator to update the Unified District Information System for Education (UDISE+) data from time to time

Identify and address dropout cases

Identify issues and counsel parents, resolve difficulties

Ensure timely re-enrolment of affected children

Prepare fortnightly reports on identified out-of-school children

The reports should include the admission status of the children, their attendance in schools and Special Training Centres, status of textbook supply, uniform, writing material, assessment status and mainstreaming plan, among others which should be provided to the Samagra Shiksha headquarters through district project offices.

According to the department's standard operating procedure for out-of-school children, their identification is done "to admit them in regular class/STC at the earliest." They should be given admission in a regular government school immediately in the age-appropriate class where learning assessment of the child is done. This is to mainstream the child as after the assessment, the child may be recommended schooling in regular class or STC for a bridge course, as per the stage of learning.

NEWS BOX

Netanyahu denounces report that Israeli soldiers have orders to shoot at Palestinians seeking aid

JERUSALEM. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz emphatically rejected a report in the left-leaning Israeli daily Haaretz on Friday, which claimed Israeli soldiers were ordered to shoot at Palestinians approaching aid sites inside Gaza. They called the report's findings "malicious falsehoods designed to defame" the military.

More than 500 Palestinians have been killed and hundreds more wounded while seeking food since the newly formed Gaza Humanitarian Foundation began distributing aid in the territory about a month ago, according to Gaza's Health Ministry.

Palestinian witnesses say Israeli troops have opened fire at crowds on the roads heading toward the sites. Reacting to the Haaretz piece, Israel's military confirmed that it was investigating incidents in which civilians had been harmed while approaching the sites. It rejected the article's allegations "of deliberate fire toward civilians."The foundation, which is backed by an American private contractor, has been distributing food boxes at four locations, mainly in the far south of Gaza, for the past month.

"GHF is not aware of any of these incidents but these allegations are too grave to ignore and we therefore call on Israel to investigate them and transparently publish the results in a timely manner," the group said in a social media post.Palestinians trying to find food have frequently encountered chaos and violence on their way to and on arrival at the aid sites. Tens of thousands are desperate for food after Israel imposed a 2 1/2 month siege on Gaza, blocking all food, water and medicine from entering the territory pending the setup of the GHF sites.

The bodies of eight people who died Friday had come to Shifa Hospital from a GHF site in Netzarim, although it was not immediately clear how they died, Dr. Mohamed Abu Selmyiha, the hospital's director, told The Associated Press. A GHF spokesperson challenged the report, saying they did not know of any incidents at or near their sites Friday.Twenty other bodies his hospital received Friday came from airstrikes across north Gaza, he said.

Protesters gather in Bangkok to demand PM Shinawatra's resignation over leaked phone call with Hun Sen

BANGKOK. Hundreds of protesters gathered in Thailand's capital on Saturday to demand the resignation of Prime Minister Paetongtarn Shinawatra, part of the brewing political turmoil set off by a leaked phone call with former Cambodian Prime Minister Hun Sen.Paetongtarn faces growing dissatisfaction over her handling of a recent border dispute with Cambodia involving an armed confrontation May 28. One Cambodian soldier was killed in a relatively small, contested area.The recorded phone call with Hun Sen was at the heart of the demonstration Saturday and has set off a string of investigations in Thailand that could lead to Paetongtarn's removal.Outrage over the call mostly revolved around Paetongtarn telling Hun Sen, the current Cambodian Senate president, not to listen to "an opponent" in Thailand. It's believed to be a reference to the regional Thai army commander in charge of the area where the clash happened, who publicly criticized Cambodia over the border dispute.

Protesters held national flags and signs as they occupied parts of the streets around the Victory Monument in central Bangkok. At a huge stage set up at the monument, speakers expressed their love for Thailand following the intensified border dispute.Many of the leading figures in the protest were familiar faces from a group popularly known as Yellow Shirts, whose clothing color indicates loyalty to the Thai monarchy. They are longtime foes of Paetongtarn's father, former Prime Minister Thaksin Shinawatra, who reportedly has a close relationship with Hun Sen.

Driven to starvation, Sudanese people eat weeds and plants to survive as war rages

CAIRO. With Sudan in the grips of war and millions struggling to find enough to eat, many are turning to weeds and wild plants to quiet their pangs of hunger. They boil the plants in water with salt because, simply, there is nothing else.Grateful for the lifeline it offered, a 60-year-old retired school teacher penned a love poem about a plant called Khadija Koro. It was "a balm for us that spread through the spaces of fear," he wrote, and kept him and many others from starving.

A.H, who spoke on the condition his full name not be used, because he feared retribution from the warring parties for speaking to the press, is one of 24.6 million people in Sudan facing acute food insecurity —nearly half the population, according to the I ntegrated Food Security Phase Classification. Aid workers say the war spiked market prices, limited aid delivery, and shrunk agricultural lands in a country that was once a breadbasket of the world.Sudan plunged into war in April 2023 when simmering tensions between the Sudanese army and its rival paramilitary the Rapid Support Forces escalated to fighting in the capital Khartoum and spread across the country, killing over 20,000 people, displacing nearly 13 million people, and pushing many to the brink of famine in what aid workers deemed the world's largest hunger crisis.Food insecurity is especially bad in areas in the Kordofan region, the Nuba Mountains, and Darfur, where El Fasher and Zamzam camp are inaccessible to the Norwegian Refugee Council, said Mathilde Vu, an aid worker with the group based in Port Sudan.

'This is not an ordinary fraud case': Funeral home owner who stashed nearly 190 decaying bodies sentenced to 20 years in prison

Federal prosecutors accused both Hallfords of pandemic aid fraud, siphoning the money and spending it and customer's payments on a GMC Yukon and Infiniti worth over \$120,000 combined, along with \$31,000 in cryptocurrency...

DENVER. A Colorado funeral home owner who stashed nearly 190 dead bodies in a decrepit building and sent grieving families fake ashes received the maximum possible sentence of 20 years in prison on Friday, for cheating customers and defrauding the federal government out of nearly \$900,000 in COVID-19 aid.Jon Hallford, owner of Return to Nature Funeral Home, pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud in federal court last year. Separately, Hallford pleaded guilty to 191 counts of corpse abuse in state court and will be sentenced in August.At Friday's hearing,

federal prosecutors sought a 15-year sentence and Hallford's attorney asked for 10 years. Judge Nina Wang said that although the case focused on a single fraud charge, the circumstances and scale of Hallford's crime and the emotional damage to families warranted the longer sentence. "This is not an ordinary fraud case," she said. In court before the sentencing, Hallford told the judge that he opened Return to Nature to make a positive impact in people's lives, "then everything got completely out of control, especially me.""I am so deeply sorry for my actions," he said. "I still hate myself for what I've done."Hallford and his wife, Carie Hallford, were accused of storing the bodies between 2019 and 2023 and sending families fake ashes. Investigators described finding the bodies in 2023 stacked atop each other throughout a squat, bug-infested building in Penrose, a small town about a two-hour drive south of Denver.The morbid discovery revealed to many families that their loved ones weren't cremated and that the ashes they had spread or cherished were fake. In two cases, the wrong body was buried, according to court documents.Many families said it undid

their grieving processes. Some relatives had nightmares, others have struggled with guilt, and at least one wondered about their loved one's soul.Among the victims who spoke during Friday's sentencing was a boy named Colton Sperry. With his head poking



just above the lectern, he told the judge about his grandmother, who Sperry said was a second mother to him and died in 2019.Her body languished inside the Return to Nature building for four years until the discovery, which plunged Sperry into depression. He said he told his parents at the time, "If I die too, I could meet my grandma in heaven and talk to her again." His parents brought him to the hospital for a

mental health check, which led to therapy and an emotional support dog."I miss my grandma so much," he told the judge through tears.Federal prosecutors accused both Hallfords of pandemic aid fraud, siphoning the money and spending it and customer's payments on a GMC Yukon and Infiniti worth over \$120,000 combined, along with \$31,000 in cryptocurrency, luxury items from stores like Gucci and Tiffany & Co., and even laser body sculpting.Derrick Johnson told the judge that he traveled 3,000 miles (4,830 kilometers) to testify over how his mother was "thrown into a festering sea of death.""I lie awake wondering, was she naked? Was she stacked on top of others like lumber?" said Johnson.While the bodies rotted in secret, (the Hallfords) lived, they laughed and they dined," he added. "My mom's cremation money likely helped pay for a cocktail, a day at the spa, a first class flight."Jon Hallford's attorney, Laura H. Suelau, asked for a lower sentence of 10 years in the hearing Friday, saying that Hallford "knows he was wrong, he admitted he was wrong" and hasn't offered an excuse.

Bangladesh government reaffirms commitment to safeguard minority rights

DHAKA. Bangladesh government has said that it remains firmly committed to safeguarding the rights of all communities and protecting places of worship but building religious structures on public land is not permissible "under any circumstance".

The Foreign Ministry's statement on Friday came a day after India denounced the reported destruction of a Durga temple in Dhaka and stressed the responsibility of Bangladesh's interim government to protect Hindus as well as religious institutions.The ministry claimed that the temple in Dhaka's Khilkhet area was built on land owned by Bangladesh Railways, and its removal was carried out following due process to recover public land, the state-run BSS news agency reported.It alleged that the temple started as a makeshift pavilion, with organisers attempting to make the temporary structure permanent despite repeated

reminders.On June 26, Bangladesh Railways proceeded with the "peaceful eviction of all unauthorised structures along the rail track in Khilkhet area," it said.

"While the laws of the land ensure full



protection to all places of worship without discriminating against any built-in conformity with law, it is not permissible for any to build any religious structure encroaching public land under any circumstances," the ministry said."Bangladesh remains firmly committed to safeguarding the

rights of all communities, including protection of the places of worship," it added.During a briefing on Thursday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "We understand that extremists were clamouring for demolishing the Durga temple in Khilkhet, Dhaka.""The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today," he said.

"This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to recur in Bangladesh," he added.Jaiswal underlined that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh "to protect Hindus, their properties, and religious institutions."The Hindu population in Bangladesh has been affected by a series of incidents against minority communities in the country.

Thousands mourn top Iranian military commanders, scientists killed in Israeli strikes

DUBAI. Thousands of mourners lined the streets of downtown Tehran on Saturday for the funeral of the head of the Revolutionary Guard and other top commanders and nuclear scientists killed during a 12-day war with Israel.

The caskets of Guard's chief Gen. Hossein Salami, the head of the Guard's ballistic missile program, Gen. Amir Ali Hajizadeh and others were driven on trucks along the capital's Azadi Street as people in the crowds chanted: "Death to Aeria" and "Death to Israel."Salami and Hajizadeh were both killed on the first day of the war, June 13, as Israel launched a war it said meant to destroy Iran's nuclear program, specifically targeting military commanders, scientists and nuclear facilities.

There was no immediate sign of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, in the state broadcast of the funeral. Khamenei, who has not made a public appearance since before the outbreak of the war, has in past funerals held prayers for fallen commanders over

their caskets before the open ceremonies, later aired on state television.Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi was on hand, and state television reported that Gen. Esmail Qaani, who heads the foreign wing of the Revolutionary Guard, the Quds Force, and Gen. Ali Shamkhani were also among the mourners.Shamkhani, an adviser to Khamenei who was wounded in the first round of Israel's attack and hospitalized, was shown in a civilian suit leaning on a cane in an image distributed on state television's Telegram channel.Iran's Revolutionary Guard was created after its 1979 Islamic Revolution. Since it was established, it has evolved from a paramilitary, domestic security force to a transnational force that has come to the aid of Tehran's allies in the Middle East, from Syria and Lebanon to Iraq. It operates in parallel to the country's existing armed forces and controls Iran's arsenal of ballistic missiles, which it has used to attack Israel twice during the Israel-Hamas war in the Gaza Strip.Over 12 days before a

ceasefire was declared on Tuesday, Israel claimed it killed around 30 Iranian commanders and 11 nuclear scientists, while hitting eight nuclear-related facilities and more than 720 military infrastructure sites. More than 1,000 people were killed, including at least 417 civilians, according to the Washington-based Human Rights Activists group.Iran fired more than 550 ballistic missiles at Israel, most of which were intercepted, but those that got through caused damage in many areas and killed 28 people.Saturday's ceremonies were the first public funerals for top commanders since the ceasefire, and Iranian state television reported that they were for 60 people in total, including four women and four children. Authorities closed government offices to allow public servants to attend the ceremonies.Iran has always insisted its nuclear program is only for peaceful purposes. But Israel views it as an existential threat and said its military campaign was necessary to prevent Iran from building an atomic weapon.

Many South Asians, Muslims in NYC and beyond electrified by Mamdani's mayoral primary triumph

World The success of Zohran Mamdani in New York City's Democratic primary for mayor is euphoric for Hari Kondabolu, a stand-up comedian who's been friends with the candidate for 15 years.

Mamdani stunned the political establishment when he declared victory in the primary on Tuesday, a ranked choice election in which his strongest competition, former New York Gov. Andrew Cuomo, conceded defeat. When he launched his campaign, the unabashed democratic socialist ranked near the bottom of the pack. Now, the 33-year-old state assemblyman has a chance to be New York City's first Asian American and Muslim mayor. Mamdani's family came to the United States when he was 7, and he became a citizen in 2018. He was born to Indian parents in Kampala, Uganda.

For Kondabolu, this moment is not just exciting, but emotional.

"I think so many of us have had those experiences in New York of being brown and in a city that has always been really diverse and feels like ours. But after 9/11, like you start to question it like, is this our city too," Kondabolu said. "And 25 years later ... it's surreal, like this is the same city but it's not because we've elected this person."Mamdani's campaign has piqued the interest of many Indian, Pakistani and other South Asian Americans, as well as Muslims — even those who may not agree with Mamdani on every issue. Despite that opposition, some still see his rise as a sign of hope in a city where racism and xenophobia erupted following the Sept. 11, 2001, terrorist attacks.

South Asians and Muslims riveted by primary in New York, and beyondMany of New York City's over 300,000 South Asian residents have been inspired by Mamdani's extraordinary trajectory."My mom was texting her friends to vote for him. I've never seen my mother do that before," Kondabolu said. "So the idea that it's gotten our whole family activated in this way — this is, like, personal."Snigdha Sur, founder and CEO of The Juggernaut, an online publication reporting on South Asians, has been fascinated by the response from some people in India and the diaspora.

"So many global South Asians ... they're like, 'Oh, this guy is my mayor and I don't live in New York City,'" Sur said.At the same time, some are also concerned or angered by Mamdani's past remarks about Indian Prime Minister Narendra Modi, who he publicly called a "war criminal."In Michigan, Thasin Sardar has been following Mamdani's ascent online. When he first heard him, he struck him as "genuine" and he felt "an instant connection," he said."As a Muslim American, this victory puts my trust back in the people," said Sardar, who was born and raised in India. "I am happy that there are people who value the candidate and his policies more than his personal religious beliefs and didn't vote him down because of the color of his skin, or the fact that he was an immigrant with an uncommon name."

New York voter Zainab Shabbir said family members in California, and beyond, have also excitedly taken note.

Pakistan welcomes Court of Arbitration's ruling on J&K hydroelectric projects

ISLAMABAD. Pakistan on Saturday welcomed the ruling by the Permanent Court of Arbitration in The Hague over two hydroelectric projects in Jammu and Kashmir and indicated its readiness for talks with India on issues relating to Indus Waters Treaty.The "high priority", at this point, is that "India and Pakistan find a way back to a meaningful dialogue, including on the application of the Indus Waters Treaty (IWT)," Pakistan said in a statement released early on Saturday.India on Friday strongly rejected the ruling saying it has never recognised the so-called framework for dispute resolution with Pakistan.

India rejects this so-called "supplemental award", the Ministry of External Affairs (MEA) said, referring to the ruling in the case related to Pakistan's objections to Kishenganga and Ratle hydropower projects.In its ruling, the Court of Arbitration said India's decision in April to keep the Indus Waters Treaty in abeyance "does not limit" its competence over the

dispute and that its ruling is binding on the parties.However, India has never recognised the proceedings at the Permanent Court of Arbitration after Pakistan raised objections to certain design



elements of the two projects under the provisions of the Indus Waters Treaty.On the other hand, Pakistan called the ruling a "major legal win" emphasising that it is a "clear message that India cannot unilaterally suspend or sideline the

treaty."The MEA called out Pakistan by saying that "this latest charade at Pakistan's behest is yet another desperate attempt by it to escape accountability for its role as the global epicentre of terrorism.""Pakistan's resort to this fabricated arbitration mechanism is consistent with its decades-long pattern of deception and manipulation of international forums," it said in a statement.The illegal Court of Arbitration, purportedly constituted under the Indus Waters Treaty 1960, albeit in brazen violation of it, has issued what it characterizes as a 'supplemental award' on its competence concerning the Kishenganga and Ratle hydroelectric projects in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir," the MEA said.

"India has never recognised the existence in law of this so-called Court of Arbitration," it said.The MEA said India's position has all along been that the constitution of this so-called arbitral body is in itself a serious

breach of the Indus Waters Treaty and consequently any proceedings before this forum and any award or decision taken by it are also illegal for that reason.A day after the April 22 Pahalgam terror attack, India took a series of punitive measures against Pakistan that included putting the Indus Waters Treaty of 1960 in "abeyance".

"Following the Pahalgam terrorist attack, India has in exercise of its rights as a sovereign nation under international law, placed the Indus Waters Treaty in abeyance, until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism," the MEA said.

"Until such time that the treaty is in abeyance, India is no longer bound to perform any of its obligations under the treaty," it said.

"No court of arbitration, much less this illegally constituted arbitral body which has no existence in the eye of law, has the jurisdiction to examine the legality of India's actions in exercise of its rights as a sovereign," it added.

On day one, 14 wickets fell, and on day two 10 wickets. Before Friday's play, Lyon said, "Every run is gold." But Australia enjoyed a gold rush from Head, who made 61, Webster 63, and Carey 56. Australia, starting on 92-4 and a lead of 2, amassed a bonus 310 total. After taking over late Thursday, Head came out firing in the morning but should have gone on 21 and be 107-5. Greaves spilled the catch at second slip off the bowling of Alzarri Joseph. It was West Indies' seventh dropped catch in the match.

Shraddha Kapoor's

Cryptic Emotional Note Leaves Fans Concerned: 'She Is Silently Struggling'

Shraddha Kapoor took to Instagram to pen a heartfelt poem about comforting someone in their sad times. The poem resurfaced on Reddit and left fans divided. While some believe that the poem is a cry for help and that the actress is expressing her loneliness, others said that it's a romantic poem that she wrote for her rumoured boyfriend Rahul Mody. The poem read, "Jab tum akele ho, Main tumhare paas baith jaungi. Jab tum udaas ho, Main tumhe baahon main bhar loongi. Mujhe pata hai tum kho jaate ho. Mujhe pata hai tum bhaag jaate ho. Lekin main tumhe dhoond loongi, aur tumhe thaam loongi."

One person wrote, "Life's complicated-even and especially for those in the public eye. They have the same insecurities as we do, but they live in a bubble, so they don't always get to touch grass. The least we can do is practice kindness towards everyone." Another added, "Life is



hard, and 2025 has particularly been hard for a lot of people. Wishing her strength." One person wrote, "I feel like Shraddha Kapoor is silently struggling. Lately, I've been noticing something different about Shraddha Kapoor. In her recent photos, her smile doesn't feel the same—it's like it's missing the spark we all used to see." Someone else wrote, "Why do I feel like this is a romantic story, not a sad one, & she is so much in love!" Another wrote, "I feel this is a message for her boyfriend." One comment read, "This feels like something her boyfriend wrote for her and not a call for help." Another added, "Idk this seems dedicated to Rahul Mody, not her being sad or anything." Someone else wrote, "Is this for her boyfriend?"

Meanwhile, Shraddha Kapoor's recent spotting outside Maddock Films' office in Mumbai stirred quite the buzz, leading to fan speculation about a possible new project with the production house. And now, reports are rife that the actress was at the office for a creative meeting with producer Dinesh Vijan, and the conversation points to an exciting reunion. The upcoming project is believed to be based on a popular Marathi novel and will showcase Shraddha in a culturally rooted role.

Shraddha Kapoor was last seen in *Stree 2*. The horror-comedy, released in 2024, starred her alongside Rajkumar Rao, Abhishek Banerjee, Aparshakti Khurana and Pankaj Tripathi. The Amar Kaushik's directorial took the box office by storm.



Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: Dilip Joshi

Munmun Dutta

Quit Asit Modi's Show?

Who does not know Jethalal and Babita ji? The iconic characters, played by Dilip Joshi and Munmun Dutta respectively in *Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah*, are widely loved by the audience. However, the current plot in the show doesn't feature the favourite pair of characters. And therefore, their absence has left everyone wondering if Dilip Joshi and Munmun Dutta have left the popular sitcom. The rumours of Dilip Joshi and Munmun Dutta's exit from



TMKOC started after fans noticed that Jethalal and Babita Ji have been missing from the current 'Bhootni' plot for a long time now. All the members of the Gokuldham society are on vacation in a haunted bungalow. While other characters like Babu ji, Popatlal, Sodhi and others have joined Taarak Mehta and Anjali on this vacation, Jethalal and Babita Ji have

been missing in action. This has left everyone wondering if Dilip Joshi and Munmun Dutta are planning to quit the show.

As reported by ABP News, the show's production house has confirmed that Munmun Dutta and Dilip Joshi are still part of the show. While the current plotline indicates that 'Jethalal' is on a business trip with his associates, 'Babita' and 'Iyer' are said to be vacationing in Mahabaleshwar. It should be noted that both Munmun Dutta and Dilip Joshi have been a part of TMKOC ever since its beginning. The former plays the role of Babita ji in the popular sitcom, and her chemistry with Jethalal (essayed by Dilip Joshi) is widely loved by all.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah has been running successfully for 17 years now. However, in these years, several actors have also left the show. Among others, Disha Vakani, Jheel Mehta, Bhavya Gandhi, Raj Anadkat, Palak Sindhvani, Gurucharan Singh Sodhi and Neha Mehta are no longer a part of TMKOC.

In a previous interview with the SCREEN, Asit Modi talked about actors leaving the show and then making allegations against him. "I have never detached myself from the actors. If there is any issue, they can always contact me. I have always been very honest and kept the show first. I have never thought of any personal gains, so with incidents like these, I do get upset, but it's a part of life," he said.



Ranveer Brar Attends Cannes Lions, Calls Experience 'Truly Magical'

The event is a global gathering of creative minds determining the future of marketing and advertising.



Chef Ranveer Brar recently graced the red carpet at the Cannes Lions International Festival of Creativity 2025, a prestigious global event that celebrates innovation in marketing and advertising. The festival gathers creative minds from across the world, recognising how imagination and storytelling can spark change, forge connections and drive progress.

Taking to Instagram, Ranveer shared a carousel capturing memorable moments from his trip to the stunning French Riviera. The first photo shows him descending a red-carpeted staircase with poise, followed by a quirky shot in front of a hotel featuring a giant Mickey Mouse installation. Another frame shows him striking a stylish pose by the beach, while the final image features him near a staircase, exuding calm confidence.

Captioning the post, Ranveer wrote, "They said Cannes is magical... turns out, it really is!"—perfectly summing up his experience at this remarkable celebration of creativity.

For the event, Ranveer opted for a white and teal deconstructed suit that combined sharp tailoring with playful, avant-garde elements including quirky prints and a feathery shoulder detail. The ensemble was from the shelves of the fashion designer Anurag Gupta.

In no time, the comment section was flooded with reactions from fans and admirers. An Instagram user wrote, "Chef with style." Another one shared, "Wonderful chef looks awesome." One of them commented, "Love the looks."

Known for his culinary art and his sense of styling, the Chef recently bagged the Most Stylish Culinary Artist of the Year 2025 award. Being one of India's most acclaimed chefs, his journey began from the backstreets of Lucknow to become one of the youngest executive chefs at a five-star hotel, before wowing viewers as a host on *MasterChef India*, *Raja Rasoi Aur Andaaz* *Anokha* and *Station Master's Tiffin*. His culinary style is based on culture, nostalgia and a great appreciation for ingredients—every dish is a tribute and each plate is a story. Recently, he appeared as a judge on the cooking-based reality show *Celebrity MasterChef* along with Chef Vikas Khanna and Farah Khan.

Disha Parmar's Mom Life Moment With Rahul Vaidya On Phone Is Relatable



Disha Parmar is melting hearts once again, this time with a slice-of-life moment that perfectly captures the sweet chaos of parenthood. The *Bade Achhe Lagte Hain 2* actress, who welcomed her baby girl Navya (fondly called Navu) in 2023 with husband Rahul Vaidya, has been sharing glimpses of their joyful family life ever since. In her latest Instagram story, Disha dropped an adorable photo featuring the trio in full-on cozy mode. While she's seen snuggling Navu on the sofa, Rahul is blissfully engrossed in his phone, offering a hilariously relatable snapshot of everyday family life. Adding the perfect soundtrack, Disha paired the image with the viral audio "If it's cute, that's it," and captioned it cheekily: "Life every day (sin) Navu & mummy clinging to each other whilst Baba is on phone (sin)."

Since becoming a mother, Disha has been open about her journey, sharing both the joys and challenges of parenting. From sweet milestones with Navya to her unwavering dedication to fitness, she continues to balance her personal and professional life with grace. Fans admire her authenticity, as she keeps them updated with heartwarming glimpses into her world.

A few weeks ago, Disha revealed how her life has been lately while throwing light on the struggles of her motherhood phase. "It's been over 2 years since I last slept well! That uninterrupted 8-9 hrs of sleep... I don't remember what that was or waking up fresh without the cries! Urgh... waiting for that to come back.

Hopefully soon!" she wrote in an Instagram post. Disha Parmar and her husband Rahul Vaidya welcomed their princess in September 2023 after being in marital bliss for almost two years. As the couple navigate this new chapter, their adorable family moments serve as a reminder of the beauty of togetherness. With Navya at the centre, this trio is undoubtedly winning hearts, one post at a time!